वर्ष 13 • अंक 31 • 8 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शनिवार 28 मार्च 2020

कोलकाता, **चंडीगढ़**, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 4

देश बंदी से एफएमसीजी कंपनियों पर असर

गुंटेर बट्सचेक ▸▸ पृष्ठ 2

यात्री और ई-वाहन कारोबार अलग करेगी टाटा मोटर्स

डॉलर रु. 74.90 ▼ 30 पैसे | यूरो रु. 82.50 ▲ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु. 43500 ▲ 390 रुपये | सेंसेक्स 29815.60 ▼ 131.20 | निफ्टी 8660.30 ▲ 18.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 8651.40 ▲ 08.80 | ब्रेंट क्रूड 24.90 डॉलर ▼ 01.30 डॉलर

कर्ज हुआ सस्ता, किस्त वसूली में भी मोहलत

कोरोना संकट से उबरने के लिए रिजर्व बैंक ने रीपो दर में 75 आधार अंक की कटौती की, रिवर्स रीपो भी 90 आधार अंक घटाया, बैंकिंग तंत्र में नकदी बढ़ाने के किए कई उपाय

अनूप रॉय
मुंबई, 27 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोरोनावायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित असर को कम करने के लिए कई उपायों की आज घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने नीतिगत रीपो दर 75 आधार अंक घटाकर 4.4 फीसदी कर दिया। साथ ही उसने सभी बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से तीन महीने तक ऋण की किस्त नहीं लेने को कहा है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'कोविड-19 संकट को देखते हुए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 31 मार्च से 3 अप्रैल तक होने वाली बैठक 24 से 26 मार्च और 27 मार्च को हुई। इसमें 4 सदस्यों ने नीतिगत रीपो दर 4.4 फीसदी करने पर सहमति जताई। बाहरी सदस्य चेतन घाटे और पमी दुआ ने 50 आधार अंक कटौती के लिए वोट दिया जबकि दास सहित अन्य सदस्य 75 आधार अंक की कटौती के पक्ष में थे। नीतिगत रुख यथावत उदार रखा गया है।

रिवर्स रीपो दर में 90 आधार अंक की कमी की गई है। यह वह दर है जिस पर बैंक अपना अतिरिक्त कोष केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं। इसकी दर में कटौती से बैंक ऐसा करने से परहेज करेंगे और इसके बजाय अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देंगे।

कदम : रीपो दर **75** आधार अंक घटाकर **4.4** फीसदी की

संभावित असर : कोविड-19 के असर को कम करने और वृद्धि में सुधार संभव

कदम : रिवर्स रीपो दर **90** आधार अंक घटाकर **4** फीसदी किया

संभावित असर : बैंक उपलब्ध कोष का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों को कर्ज देने में कर सकते हैं

कदम : अधिकतम **3** साल के लिए आएंगे लक्षित दीर्घावधि के रीपो

संभावित असर : डेट पूंजी बाजार में बढ़ेगा निवेश

कदम : एनडीटीएल के सीआरआर को **100** आधार अंक घटाकर **3** फीसदी किया

संभावित असर : बैंकिंग तंत्र में **1.37** लाख करोड़ रुपये की बढ़ेगी नकदी

कदम : एमएसएफ के तहत समायोजन एसएलआर के **2** फीसदी से बढ़ाकर **3** फीसदी किया

संभावित असर : अतिरिक्त **1.37** लाख करोड़ रुपये की तरलता बढ़ेगी

कदम : टर्म लोन की वसूली **3** महीने टालने का निर्णय

संभावित असर : ग्राहकों पर कर्ज भुगतान का बोझ कम होगा

कदम : कार्यशील पूंजी पर ब्याज को **3** महीने के लिए टाला गया

संभावित असर : कंपनियों पर दबाव घटेगा

रीपो दर में कटौती

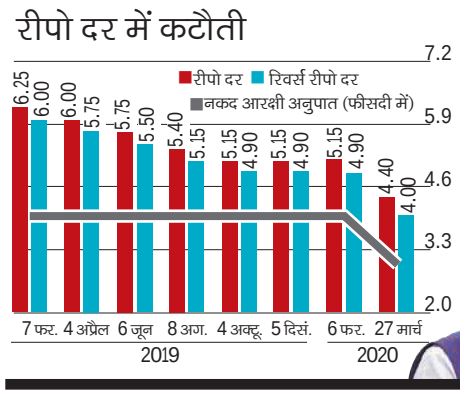

इन घोषणाओं से बाजार में तरलता की स्थिति बेहतर होगी, कर्ज की ब्याज दरें कम होंगी तथा मध्यम वर्ग और कारोबारियों को मदद मिलेगी।

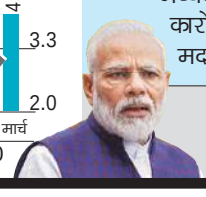

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

कर्ज किस्तों के भुगतान और कार्यशील पूंजी के ब्याज पर तीन महीने के लिए रोक लगाना राहत भरा कदम है। ब्याज दरों में कमी का लाभ ग्राहकों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाना चाहिए।

निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री

मुद्रास्फीति बनाम वृद्धि

भारी उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित अनिश्चितता और बेहद मुश्किल हालात में केंद्रीय बैंक वृद्धि और महंगाई के आंकड़ों का अनुमान जताकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। आरबीआई गवर्नर ने चेतावनी दी कि अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस के असर को देखते हुए इस वित्त वर्ष के दौरान 5 फीसदी की सालाना विकास दर का अनुमान खतरे में है।

विकास और महंगाई का अनुमान इस बात पर निर्भर करेगा कि कोविड-19 का क्या असर रहता है, यह कितना फैलता है और कितने समय तक रहता है। यही वजह है कि मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई और विकास के बारे में कोई अनुमान जताने से परहेज किया।

दास ने कहा कि खाद्य महंगाई में आने वाले दिनों में गिरावट आने की संभावना है लेकिन कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को छोड़कर अर्थव्यवस्था को अधिकांश क्षेत्रों के कोरोनावायरस के कारण बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रसार कितना और कितने समय तक रहता है। उन्होंने कहा, 'समिति का मानना है कि कोरोनावायरस के कारण मांग और आपूर्ति, दोनों तरफ वृहद आर्थिक जोखिम व्यापक हो सकते हैं। अभी जरूरत इस बात की है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हरसंभव उपाय किए जाएं।'

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को लोगों के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए क्योंकि वायरस के कारण वे अलग-थलग पड़ गए हैं। साथ ही बाजारों को भी अपना काम जारी रखना चाहिए और इस स्थिति से निपटने के लिए मजबूत वित्तीय उपाय बेहद जरूरी हैं। दास ने कहा कि बैठक में जो फैसले लिए गए वे कोरोनावायरस की भयावहता को देखते हुए जरूरी हैं। इनका मकसद वायरस के नकारात्मक प्रभावों को कम करना, विकास को पटरी पर लाना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

एसबीआई ने उधारी दर 75 आधार अंक घटाई

अभिजित लेले और सोमेश झा
मुंबई, 27 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग तंत्र में भारी-भरकम नकदी डालने की पहल की है। इसे देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी उधारी दरों में 75 अंक की कटौती कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी।

इसके साथ ही खुदरा सावधि जमा पर ब्याज दरों में 20 से 50 आधार अंक की भी कटौती की गई है। बल्क जमाओं की ब्याज दर में 50 से 100 आधार अंक की कटौती की गई है। बाह्य बेंचमार्क से जुड़ी उधारी दर भी 7.80 से घटकर 7.05 फीसदी रह जाएगी। रीपो से जुड़ी उधारी दर 7.40 फीसदीस से कम होकर 6.65 फीसदी हो जाएगी।

एसबीआई ने कहा कि 1 लाख रुपये का 30 साल के लिए होम लोन पर मासिक किस्त 52 रुपये कम हो जाएगी। खुदरा ऋणों और एसएमई के लिए बाह्य बेंचमार्क से जुड़े कर्ज को भी इस कटौती का पूरा लाभ मिलेगा। एसबीआई ने कहा, '20 अप्रैल को एलसीओ की होने वाली बैठक में एमसीएलआर पर चर्चा की जाएगी। जमा दरों में कटौती एमसीएलआर की अगली बैठक के बाद परिलक्षित होगी।'

अन्य बैंक की जल्द ही दरों में कटौती के कदम उठा सकते हैं और विभिन्न तरह के कर्ज पर ब्याज दरों में 75 से 100 आधार अंक की कटौती की जा सकती है। अधिकांश बैंक अप्रैल से कटौती को प्रभावी कर सकते हैं।

बैंकों को उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक जमा दरों में 25 से 50 आधार अंक की कमी हो सकती है। रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात में भी कटौती की है, जिससे बैंकिंग तंत्र में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी आएगी।

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि उनके बैंक के पास उधार देने और निवेश परिचालनों के लिए 31,000 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि जिन छह बैंकों का विलय होना है, उनके एंकर बैंक दरों में कटौती पर निर्णय करेंगे। सिंडिकेट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि रीपो से जुड़े ऋण के ब्याज दरों में कमी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। हालांकि एमसीएलआर में अभी कटौती नहीं होगी। कोविड-19 से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां टर्म लोन पर किस्तों के भुगतान में तीन महीने की मोहलत दे सकती हैं।

रजनीश कुमार
चेयरमैन, एसबीआई

- कर्ज पर ब्याज दर में 75 आधार अंक की कटौती की
- नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी
- जमा दरों में भी 20 से 100 आधार अंक की कमी
- अन्य बैंक भी जल्द घटा सकते हैं ब्याज दर

एक नज़र

दो महीने में भारत लौटे 15 लाख यात्रियों की निगरानी

पिछले दो महीने में देश में हवाई मार्ग से 15 लाख यात्री भारत आए हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने सभी राज्यों को 18 जनवरी से 23 मार्च के बीच भारत आए सभी ऐसे लोगों पर तत्काल निगरानी बढ़ाने को कहा। गाबा ने कहा कि विदेश से जिन लोगों पर नजर रखी जा रही है और उक्त अवधि के दौरान जितने लोग आए हैं उनकी संख्या में अंतर दिख रहा है। एक अन्य घोषणा में सरकार ने कृषि उपकरणों की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को लॉकडाउन से मुक्त रखा है। इस बीच, देश में कोरोनावायरस के संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 786 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 19 तक पहुंच चुकी है।

मूडीज ने वृद्धि का अनुमान घटाकर 2.5 प्रतिशत किया

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज ने इससे पहले वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। कोरोनावायरस संकट को लेकर मूडीज ने कहा कि इससे वैश्विक अर्थव्यस्था को अभूतपूर्व झटका लगेगा। कोरोनावायरस और उसके चलते देश दुनिया में आवागमन पर रोक के मद्देनजर आर्थिक लागत बढ़ी और इसी वहज से देश की वृद्धि दर घटने का अनुमान है।

तेल के दाम 22 डॉलर से नीचे आए

विभिन्न देशों की सरकार द्वारा कोरोनावायरस से निपटने के लिए घोषित राहत उपाय तेल की धार मजबूत नहीं कर पाए हैं। शुक्रवार को मांग घटने की आशंका के बीच तेल के दाम में कमी देखी गई। अमेरिका में हालात लगातार खराब हो रहे हैं और यह वायरस के संक्रमण का केंद्र बनता जा रहा है। शुक्रवार को कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड 4.8 प्रतिशत गिरकर 25.08 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। इसी तरह, अमेरिका में क्रूड 3.7 प्रतिशत फिसलकर 21.76 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

मौजूदा विदेश व्यापार नीति 30 सितंबर तक लागू रहेगी

सरकार मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015-20) की अवधि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने जा रही है। कोरोनावायरस संकट और तीन सप्ताह के देश व्यापी लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली थी। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा नीति के तहत जो भी योजनाएं चल रही हैं, वे अब 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके साथ ही निर्यातकों के लिए कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन कोरोनावायरस से संक्रमित

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को बताया कि वह कोरोनावायरस से संक्रमित हैं। जॉनसन ने ट्वीटर पर कहा कि पिछले 24 घंटे में उन्हें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण थे और जांच के बाद वह वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं को एकांतवास में रखा है, लेकिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉनसन के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है और कहा है कि वह उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

व्यापार गोष्ठी

मौजूदा हालात में कैसे थमे आर्थिक गिरावट?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें gosthti@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या आरबीआई के बाद बैंक तेजी से घटाएंगे कर्ज की दर

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या केंद्र द्वारा घोषित राहत पैकेज	हां	25.00%
मौजूदा संकट के लिए पर्याप्त है?	नहीं	75.00%

कर्मचारियों को 25 फीसदी ज्यादा वेतन देगी कॉग्निजेंट

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 27 मार्च

कोविड-19 की वजह से देश भर में बंदी के दौरान अपने कर्मचारियों की मदद के लिए कॉग्निजेंट ने अप्रैल महीने में कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 25 फीसदी अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय किया है। हालांकि यह लाभ भारत और फिलीपींस के एसोसिएट स्तर के कर्मचारियों को ही मिलेगा। कंपनी ने कहा कि वह इस पहल का मासिक आधार पर समीक्षा करेगी।

भारत में काम करने वाले कंपनी के करीब दो-तिहाई कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। 31 दिसंबर, 2019 तक देश भर में कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या करीब 2,03,700 थी। कंपनी के भारत में 13 शहारों में कई कार्यालय हैं।

कॉग्निजेंट के मुख्य कार्याधिकारी ब्रायन हम्परीज ने कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा है, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। फिलीपींस में आपातकाल की स्थिति है। हम इन कदमों का समर्थन करते हैं। वैश्विक महामारी से उद्योग की मांग भी प्रभावित हो सकती है, वहीं हम जानते हैं कि जरूरतों को पूरा करना खासा अहम होगा।'

कंपनी ने अपने अधिकतर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए घर से काम करने की अनुमति दी है। घर से काम करने के लिए कंपनी ने नए लैपटाप और डेस्कटॉप के साथ ही अतिरिक्त बैंडविड्थ कनेक्टिविटी की सुविधा दी है।

- कर्मचारियों को अप्रैल में मूल वेतन का 25 फीसदी अधिक वेतन मिलेगा
- भारत और फिलीपींस में एसोसिएट स्तर तक के कर्मचारी होंगे लाभान्वित
- भारत में करीब दो-तिहाई कर्मचारियों को होगा फायदा
- देश भर में कंपनी के करीब 2,03,700 कर्मचारी हैं

उन्होंने कहा, 'भारत और फिलीपींस में हमारे एसोसिएट की सेवाओं को जारी रखने के असाधारण प्रयासों का हम सम्मान करते हैं। इन कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हमने अप्रैल में मूल वेतन का 25 फीसदी अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय किया है। इस प्रक्रिया की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।' कॉग्निजेंट ने कहा कि सभी वैश्विक कंपनियां लंदन से लेकर मुंबई, मनीला से लेकर न्यूयॉर्क तक इस वैश्विक महामारी के असर को महसूस कर रही हैं। हम्परीज ने कहा, 'हम एक ऐसे संकट से जूझ रहे हैं जो हर दिन नई चुनौतियां लेकर आ रही है।'

कामगारों की मदद की हो रही तैयारी

सोमेश झा और अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 27 मार्च

केंद्र सरकार देशभर में जगह-जगह फंसे प्रवासी कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने की अनुमति देने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया है जिसके कारण बसों और ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। इसके कारण प्रवासी कामगार अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। केंद्र सरकार जिस योजना पर काम कर रही है उसके मुताबिक राज्यों को प्रवासी कामगारों के स्वास्थ्य की जांच के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं। उनके लिए सड़क मार्ग से परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि उसने उन प्रवासी कामगारों के लिए परिवहन और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जो शहरों में कोरोनावायरस के फैलने की आशंका के कारण अपने घर जाना चाहते हैं।

देश की निजी विमानन कंपनियों स्पाइसजेट, इंडिगो और गोएयर ने भी प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है। राज्य सरकारें भी अपनी बस सेवाएं चलाने के लिए केंद्र से मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। केंद्र ने बुधवार को 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी जिसके बाद शहरों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों का पलायन शुरू हो गया था।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहाए इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय में विचार विमर्श हो रहा है। कुछ प्रवासी कामगारों को अपने घर तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे उन राज्यों में फंस गए हैं जहां वे लंबे समय से काम कर रहे थे। कुछ राज्य सरकारों ने इन कामगारों के वापस लाने के लिए बसों के परिचालन की अनुमति देने का अनुरोध किया है। राज्य प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि अधिकारी ने कहा कि प्रवासी कामगारों के कारण वायरस के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का खतरा भी है। मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि वह दिल्ली में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को लाने की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। लेकिन बुधवार रात को देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के कारण राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसे बस सेवा संचालित करने की अनुमति नहीं मिली। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि प्रवासी कामगारों की एक सूची तैयार की जा रही है जो फंसे हुए हैं और उम्मीद है कि शनिवार तक पहली बस सेवा शुरू हो जाएगी।

फोटो : दलीप कुमार

- लॉकडाउन होने से काम बंद, बड़ी संख्या में अपने घर लौटने को मजबूर दिहाड़ी मजदूर
- सरकार इन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की कर रही तैयारी

गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ एक संवाद में प्रवासी कामगारों की मुश्किलों को स्वीकार किया। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा, 'मैं इस बात से वाकिफ हूं कि राज्य इस बारे में कई कदम उठा रहे हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र के कामगारों खासकर प्रवासी मजदूरों में बेचैनी है। इस स्थिति पर तुरंत काम करने की जरूरत है।'

निजी विमानन कंपनियों प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए मदद की पेशकश की है लेकिन सरकार ने अब तक इसे कोई भाव नहीं दिया है।

दो अन्य निजी विमानन कंपनियों-गोएयर और इंडिगो ने भी सरकार से कहा है कि वह कामगारों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए अपने विमानों का इस्तेमाल करने को तैयार है। इंडिगो के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) धनंजय दत्ता ने नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बताया, 'देश में संकट की इस घड़ी में इंडिगो लोगों की जान बचाने में सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है।' हालांकि कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि सरकार ऐसी उड़ानों की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। (शेष पृष्ठ 8 पर)

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को सहारा

अनूप रॉय
मुंबई, 27 मार्च

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की मुश्किलें दूर करने और नकदी के समाधान के आरबीआई के कदम से भारतीय कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को राहत मिली है क्योंकि ऐसी प्रतिभूतियों की खरीदारी की खातिर बैंकों के लिए एक लाख करोड़ रुपये की नकदी की सुविधा से प्रतिफल में काफी गिरावट आई।

आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि वह लक्षित लंबी अवधि के रीपो परिचालन के जरिये बैंकों को एक लाख करोड़ रुपये देगा, जो तीन साल तक की परिपक्वता अवधि वाले निवेश श्रेणी कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक प्रतिभूतियों और गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों में निवेश के लिए होगा। यह 27 मार्च 2020 को इन बॉन्डों में निवेश के बकाया स्तर के ऊपर होगा।

आरबीआई गवर्नर ने अपने भाषण में कहा कि केंद्रीय बैंक यह जरिया इसलिए अपना रहा है क्योंकि कोविड-19 के खौफ ने परिसंपत्ति वर्गों में काफी ज्यादा बिकवाली को हवा दी है और निवेश निकासी के गहराते दबाव के साथ कॉरपोरेट बॉन्डों, वाणिज्यिक प्रतिभूतियों और ऋणपत्रों जैसी प्रतिभूतियों में नकदी की जरूरत बढ़ी है। उधारी की रफ्तार में गिरावट वाले माहौल में यह कंपनियों को कार्यशील पूंजी के लिए कर्ज तक पहुंच में मुश्किलें पैदा कर रही है।

25,000 करोड़ रुपये की पहली नीलामी शुक्रवार को हुई और बैंकों ने

बॉन्ड बाजार

- 25,000 करोड़ रुपये की पहली नीलामी शुक्रवार को हुई और बैंकों ने इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई
- इस चैनल से जुटाई गई रकम को 15 दिन के भीतर निवेश करना होगा
- इसकी आधी खरीद प्राथमिक बाजार से करनी होगी और बाकी आधी द्वितीयक बाजार से, जिसमें एनबीएफसी और म्युचुअल फंड से खरीद शामिल है
- मार्च 2022 में परिपक्व होने वाले एचडीएफसी के बॉन्ड का प्रतिफल 8.25 से घटकर 6.60 फीसदी रह गया
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगस्त 2022 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड का प्रतिफल 8.55 फीसदी से घटकर 7.25 फीसदी रह गया

इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई। इस चैनल से जुटाई गई रकम को 15 दिन के भीतर निवेश करना होगा। इसकी आधी खरीद प्राथमिक बाजार से करनी होगी और बाकी आधी खरीद द्वितीयक बाजार से, जिसमें एनबीएफसी और म्युचुअल फंड से खरीद शामिल है।

आरबीआई के इस कदम से द्वितीयक बाजार में बॉन्ड प्रतिफल में तेज गिरावट आी, लेकिन यह मोटे तौर पर बेहतर रेटिंग वाले बॉन्डों में ही प्रतिबिंबित हुई।

मार्च 2022 में परिपक्व होने वाले एचडीएफसी लिमिटेड के बॉन्ड का प्रतिफल 8.25 फीसदी से घटकर 6.60 फीसदी रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अगस्त 2022 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड का प्रतिफल 8.55 फीसदी से घटकर 7.25 फीसदी रह गया जबकि एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस का अगस्त 2022 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड का प्रतिफल गुरुवार को 8.70 फीसदी था, जो आरबीआई की घोषणा के बाद 7.20 फीसदी रह गया।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ (इंडिया) जरीन दारुवाला ने कहा, आरबीआई का एलटीआरओ क्रेडिट चैनल में भीड़भाड़ कम करेगा और उधारी लागत भी घटाएगा, जो कंपनियों को काफी राहत देगा, जिसकी उन्हें जरूरत थी।

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) बद्रीश कुलहल्ली के मुताबिक, आरबीआई के कदम से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का दबाव घटेगा। उन्होंने कहा, प्रतिभागियों की संख्या घटी थी क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में फंडिंग की उपलब्धता पर संदेह बढ़ रहा था, खास तौर से साल के आखिर में। आरबीआई का यह कदम इस खाई को पाटेगा और कॉरपोरेट बॉन्ड के प्रतिफल में पहले ही गिरावट आ चुकी है। चूंकि बाजार सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है, उधार लेने वाले कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में फंडिंग की उपलब्धता पाएंगे। कुलहल्ली ने कहा, हालांकि क्रेडिट के जोखिम वाले माहौल में शुरुआती इश्यू अग्रणी रेटिंग वाली कंपनियों से ही देखने को मिल सकते हैं।

डेट म्युचुअल फंडों को होगा बड़ा फायदा

जश कृपलानी
मुंबई, 27 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रीपो दरों में 75 आधार अंकों की कटौती के बाद डेट फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, साथ ही वे लिक्विड योजनाओं से निवेश निकासी को संभालने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे क्योंकि आरबीआई बैंकों को कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में और नकदी झोंकने को कह रहा है।

सुंदरम एमएफ के मुख्य निवेश अधिकारी (फिक्स्ड इनकम) द्विजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, इस कदम से मौजूदा निवेशकों के डेट पोर्टफोलियो का दोबारा मूल्यांकन हो जाएगा क्योंकि प्रतिफल में नरमी आएगी।

अल्पावधि वाले बॉन्ड बाजार का प्रतिफल (जहां हाल के दिनों में नकदी काफी कम हो गई थी) शुक्रवार को आरबीआई के 3.74 लाख करोड़ रुपये की नकदी के कारण 150-200 आधार अंक घटा है।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि आरबीआई के कदम से देसी बॉन्ड बाजारों में ट्रेडिंग की गतिविधियों को बहाल हुई है, जो जोखिम के कारण करीब-करीब थम गई थी।

कोरोनावायरस के प्रसार के बीच आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के असर को कम करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय बैंक ने रीपो दर घटाकर 4.4 फीसदी कर दी। ब्याज दर घटाने के अलावा केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह एक लाख करोड़ रुपये तक के टर्म रीपो की नीलामी करेगा। इसके तहत ली जाने वाली नकदी बैंकों को निवेश श्रेणी वाले कॉरपोरेट बॉन्डों,

वाणिज्यिक प्रतिभूतियों और गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों में लगानी होगी।

इसके अलावा बैंकों को प्राथमिक बाजार में जारी होने वाले पात्र प्रतिभूतियों का 50 फीसदी लेना होगा और बाकी 50 फीसदी द्वितीयक बाजार से, जिसमें म्युचुअल फंड और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियां शामिल हैं।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि इससे 5 लाख करोड़ रुपये वाली लिक्विड फंड श्रेणी को मदद मिलेगी, जहां काफी ज्यादा निवेश निकासी की संभावना है क्योंकि लॉकडाउन के बीच रोजाना के परिचालन में अवरोध के कारण कंपनियां अपना लिक्विड निवेश निकालना चाह रही हैं। पिछले हफ्ते एमएफ उदद्योग ने भी नकदी सहायता के लिए आरबीआई को पत्र लिखा था।

फंड मैनेजरों ने कहा कि अल्पावधि वाली योजनाएं केंद्रीय बैंक के नकदी बढ़ाने वाले कदमों से फायदा उठाने में बेहतर स्थिति में हैं।

पीजीआईएम इंडिया एमएफ के मुख्य निवेश अधिकारी (फिक्स्ड इनकम) कुमारेश रामकृष्णन ने कहा, अल्पावधि वाली योजनाओं में सकारात्मकता देखने को मिलेगी क्योंकि व्यवस्था में नकदी वापस आने के बाद अब स्प्रेड सही स्तर पर आ जाएगा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के बीच पहले बाजार में प्रतिफल में 150-200 आधार अंकों की बढ़ोतरी दिखी थी। बाजार के प्रतिभागियों के मुताबिक, एफआईआई ने इस क्षेत्र में 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये के निवेश बेचे, वहीं देसी बाजार में खरीदारी घटी है और लॉकडाउन ट्रेडरों के लिए कीमत पर असर डाल रही है और वॉल्यूम पर भी। अब तक एफआईआई की कुल बिकवाली मार्च में 57,000 करोड़ रुपये की रही है।

इसके परिणामस्वरूप लिक्विड योजनाओं व डेट की अन्य योजनाओं के रिटर्न पर असर पड़ा। नकदी सिकुड़ने के बीच लिक्विड योजनाओं का रिटर्न नकारात्मक रहा। अन्य अल्पावधि वाली श्रेणियों पर भी असर पड़ा क्योंकि निचले से मध्यम अवधि वाली योजनाओं का रिटर्न एक से तीन फीसदी तक नीचे रहा।

उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि आरबीआई के कदमों में फंडिंग की कुल लागत कम करने की क्षमता है और मौजूदा चुनौतियों से उबरने में अर्थव्यवस्था को मदद करने की भी।

बिड़ला सन लाइफ एमएफ के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी ए बालासुब्रमण्यन ने कहा, लक्षित लंबी अवधि के रीपो परिचालन सुविधा से अल्पावधि वाली दरों पर दबाव हटाने में मदद मिलेगी। निवेश श्रेणी वाले सभी बॉन्ड कवर हुए हैं, इसका मतलब बीबीबी क्रेडिट से ऊपर वाले सभी बॉन्ड इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और अल्पावधि वाली दरों में और भागीदारी देखने को मिलेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने खोला पिटारा

पृष्ठ-1 का शेष

दरों में कटौती के अलावा नकदी और उधारी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए भी कई उपाय किए गए। इनमें आम आदमी को ऋण की किस्त के भुगतान में तीन महीने की राहत देना शामिल है।भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि उनका बैंक लंबी अवधि के ऋण पर तीन महीने तक किस्त की मांग नहीं करेगा। उन्होंने कहा, 'टर्म लोन पर किस्त अपने आप तीन महीने पीछे चली जाएगी और उपभोक्ताओं को इसके लिए बैंकों में आवेदन नहीं करना पड़ेगा।'

आरबीआई ने मौजूदा स्थिति को असाधारण और अभूतपूर्व बताया जिसमें सबकुछ कोविड-19 की भयावहता, प्रसार और समय पर निर्भर करता है। दास ने कहा, 'जाहिर है कि वायरस के खिलाफ जंग में हमें युद्ध स्तर पर प्रयास की जरूरत है और ऐसा ही किया जा रहा है। इसमें परंपरागत और गैर-परंपरागत दोनों तरह के उपायों की जरूरत है। कोरोनावायरस के कारण अप्रत्याशित नुकसान हुआ है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए की बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता है। मजबूत लोग और मजबूत संस्थान ऐसे समय का डटकर मुकाबला करते हैं।'बॉन्ड बाजार आरबीआई के इस कदम से सकते में दिखा। केंद्रीय बैंक की घोषणा के बाद बॉन्ड प्रतिफल में अल्पावधि में 30 से 35 आधार अंक और दीर्घावधि में 15 आधार अंक की तेजी आई।

एचएसबीसी इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी और आयुषी चौधरी ने एक नोट में लिखा, 'बैंकिंग सेक्टर में पर्याप्त नकदी को देखते हुए रिवर्स रीपो रेट अब ज्यादा कारगर हो सकता है। वास्तव में यह कटौती 75 आधार अंक से ज्यादा है। शायद 75 से 115 आधार अंक के बीच।'

केंद्रीय बैंक के उपायों से नाखुश नजर आया इक्विटी बाजार

बाजार अभी भी आर्थिक वृद्धि, औपचारिक क्षेत्रों की आय और बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित है

विशाल छाबड़िया
मुंबई, 27 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणाओं को भले ही विशेषज्ञ शानदार, सराहनीय, अप्रत्याशित या 'संपूर्ण पैकेज' कह रहे हों लेकिन शेयर बाजार ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी।

बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दिन की शुरुआत में ही सबसे अधिक चढ़े। एक दिन के कारोबार में 9,038.9 अंकों की ऊंचाई तक चढ़ने के बाद निफ्टी 50 केवल 0.22 प्रतिशत या 8,660.25 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। जबकि गुरुवार को यह 8,641.45 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक सूचकांक एक दिन के कारोबार के अपने अधिकतम स्तर 21,462.4 से करीब 7 प्रतिशत गिरकर 19,969 पर बंद हुआ। हालांकि यह एक दिन पहले के स्तर से 1.8 प्रतिशत अधिक है।

तो केंद्रीय बैंक के उपायों पर दलाल स्ट्रीट ने इतनी सुस्त प्रतिक्रिया क्यों दी ?

पहला तो यह कि सोमवार को बाजार बंद होने से शुक्रवार के एक दिन के उच्चतम स्तर तक निफ्टी तथा निफ्टी बैंक जैसे प्रमुख सूचकांकों में 18.8 प्रतिशत तथा 26.9 प्रतिशत की तेजी आई है और निवेशकों ने इसके चलते प्रॉफिट बुकिंग की।

लेकिन अहम तथ्य यह है कि बाजार अभी भी आर्थिक वृद्धि, औपचारिक क्षेत्रों की आय और बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित है।

भविष्य की वृद्धि पर स्पष्टता की कमी की वजह से भी चिंताएं पैदा हुई हैं। अपने दृष्टिकोण में आरबीआई ने कहा, 'कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में थोड़े लचीलेपन के अलावा अर्थव्यवस्था के अधिकांश दूसरे क्षेत्रों में महामारी की तीव्रता, प्रसार एवं अवधि के आधार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि कोविड-19 लंबे समय तक रहती है और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो वैश्विक मंदी के गहराने के साथ ही भारत पर इसका गंभीर असर होगा।'

आरबीआई द्वारा घोषित किए गए उपाय गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से अलग हैं। केंद्र द्वारा घोषित पैकेज में

कमजोर वर्गों के लिए नकदी हस्तांतरण, खाद्य सुरक्षा आदि शामिल हैं।

हालांकि इन प्रयासों के बावजूद हालिया अनुमान कम अवधि में बेरंग तस्वीर ही पेश कर रहे हैं। एचएसबीसी द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया, 'वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में आर्थिक वृद्धि धीमी रहने की उम्मीद है हालांकि दूसरी छमाही में मांग में तेजी आने की उम्मीद है। अनुमानों के लेकर अधिक आशावादी एक घरेलू ब्रोकरेज का कहना है कि पहली तिमाही पर इसका असर होगा और सितंबर तिमाही से रिकवरी की उम्मीद है।'

वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2-5-3.5 प्रतिशत तक आने की उम्मीद है जबकि वित्त वर्ष 2020 के लिए 5 प्रतिशत अनुमानित थी। हालांकि आरबीआई ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आगे उचित कदम उठाएगा लेकिन इन सभी घोषणाओं के बाद भी इक्विटी बाजार गिर गए।

हालांक अभी भी केंद्र सरकार और आरबीआई से कुछ और उपायों की उम्मीद की जा रही है, जिसे लेकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जेएम फाइनैंशियल ग्रुप के प्रबंध निदेशक विशाल कम्पानी आरबीआई के इस कदम को सही दिशा में उठाया गया पहला कदम बताते हुए कहते हैं, 'एनबीएफसी सहित प्रत्येक क्षेत्र के लिए और ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है। आरबीआई द्वारा दिए गए सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण से भी आगे बड़े कदम उठाने का संकेत मिलता है।'

ईएमआई रियायत से अस्थायी राहत से बैंकों पर दबाव पड़ने के आसार

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 27 मार्च

शुक्रवार को आरबीआई द्वारा ऋणों की ईएमआई पर 3 महीने की रोक की घोषणा को देशव्यापी लॉकडाउन से मुकाबले के लिए बेहद जरूरी करार देते हुए बैंकों और उद्योग के पर्यवेक्षकों ने कहा कि इससे बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता के संदर्भ में जरूरी राहत मिलेगी। चूंकि कई बैंक इसे लेकर आशंकित हैं कि लॉकडाउन के प्रभाव की वजह से उनके ग्राहकों की अदायगी क्षमता प्रभावित हो सकती है, लेकिन शुक्रवार की पहल से इस तरह की आशंका दूर हो गई है।

फेडरल बैंक में रिटेल लेंडिंग ऐंड काड्र्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीलुफर मुलानफिरोज का कहना है, 'यदि ग्राहकों और कंपनियों के लिए ब्याज का बोझ तीन महीने के लिए घटता है तो इसका बैंकों और उनके ग्राहकों पर सकारात्मक असर पड़ेगा।' हालांकि इससे चुनौती भी जुड़ी होगी। स्पार्क कैपिटल के अभिनेश विजयराज का मानना है कि इससे बैंकों की बुक वैल्यू या नेटवर्थ 0.5-2 प्रतिशत तक प्रभावित होगी, वैसे यह ईएमआई

विश्लेषकों को बैंकों की बुक वैल्यू पर 0.5-2 प्रतिशत प्रभाव पड़ने और गैर-ब्याज आय में बड़ी गिरावट का अनुमान

रोक के विकल्प को अपनाने वाले ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करेगा। इसलिए, बैंकों को परिसंपत्ति गुणवत्ता दबाव का सामना नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन उनकी आय के विवरण पर दबाव दिखने की आशंका है।

जिस अन्य पहलू पर ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी वह है अल्पावधि परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)। आप यह कह सकते हैं कि बैंकों को 75 आधार अंक की रीपो दर कटौती और 90 आधार अंक की रिवर्स रीपो कटौती का लाभ मिलेगा जिससे देनदारियों को कम दर पर पुनर्गठित करना जरूरी होगा, जिसमें परिसंत्तियां अपेक्षित आय हासिल नहीं करेंगी, लेकिन यह बैंकों की तेजी से दरें बदलने की क्षमता पर निर्भर करेगा। एक निजी बैंक के ट्रेजरी प्रमुख ने कहा, 'सभी इंस्ट्रूमेंट कम दरों को स्वत: समायोजित नहीं करते हैं जिससे बैंकों के मुनाफे पर कुछ दबाव पड़ सकता है।' इसके अलावा, नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) में कमी से भी बैंकों को बफर तैयार करने और एएलएम संबंधित असमानता को दूर करने के लिए ज्यादा पूंजी हाथ में आएगी। विश्लेषकों का कहना है कि बैंकों को आरबीआई निर्देश में कहा गया है कि यह अतिरिक्त राहत उन्हें ऋण वृद्धि की रफ्तार मजबूत बनाने के लिए ही दी गई है।

कम गैर-ब्याज आय के तौर पर भी बैंकों को झटका लग सकता है। गैर-ब्याज आय को ग्राहकों द्वारा किए गए सौदों से मदद मिलती है और बैंक अक्सर ग्राहक से निर्धारित शुल्क वसूलते हैं। कमजोर शुद्ध ब्याज आय के परिवेश में, गैर-एनआईआई राजस्व से बैंकों को भारी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, एचडीएफसी बैंक, ऐक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे निजी बैंकों और बैंक ऑफ बड़ौदा तथा भारतीय स्टेट बैंक जैसे सरकारी बैंकों ने भी पिछली तीन तिमाहियों में एनआईआई राजस्व के मुकाबले गैर-एनआईआई राजस्व में अच्छी वृद्धि दर्ज की है।

स्टैंडर्ड लाइफ अबरदीन ने एचडीएफसी लाइफ में बेची 2.5 फीसदी हिस्सेदारी

समी मोडक
मुंबई, 27 मार्च

स्टैंडर्ड लाइफ अबरदीन ने आज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी 2.5 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी। ब्रिटेन की इस कंपनी ने 441.2 रुपये प्रति शेयरों भाव पर 5 करोड़ शेयरों की बिक्री से 2,200 करोड़ रुपये जुटाए।

इस बिक्री से पहले एचडीएफसी के सह-प्रवर्तक स्टैंडर्ड लाइफ की निजी क्षेत्र की इस जीवन बीमा कंपनी में 14.73 फीसदी हिस्सेदारी थी। शेयरों की कीमत गुरुवार के वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) से लगभग 7 फीसदी और तीन दिनों के वीडब्ल्यूएपी से 3 फीसदी अधिक थी। चुनौतीपूर्ण बाजार परिदृश य के बावजूद यह शेयर बिक्री सफल रही।

बाजार सूत्रों का कहना है कि निवेशकों से पूछताछ किए जाने के बाद निवेश बैंकरों ने लेनदेन शुरू किया। एक निवेश बैंकर ने कहा, 'प्रमुख निवेशकों से जबरदस्त मांग के कारण हमें द्वितीयक बाजार में उथल-पुथल के बावजूद लेनदेन करने में मदद मिली।' नवंबर 2017 में एचडीएफसी लाइफ के सूचीबद्ध होने के बाद स्टैंडर्ड लाइफ अबरदीन द्वारा विनिवेश का यह पांचवां दौर था। कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के फैलने के मद्देनजर बिकवाली बढ़ने से एचडीएफसी लाइफ का शेयर 2020 के अपने उच्च स्तर से लगभग 50 फीसदी लुढ़क चुका है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर करीब 8 फीसदी की गिरावट के साथ 440 रुपये पर बंद हुआ।

विशेषज्ञों का कहना है कि एचडीएफसी लाइफ के इस लेनदेन से बाजार को यह संकेत भेजने में मदद मिलेगी कि भारतीय इक्विटी पूंजी बाजार की रफ्तार बरकरार रहेगी। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इस सौदे के लिए निवेश बैंकर था।

यात्री वाहन व इलेक्ट्रिक कारोबार अलग करेगी टाटा

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 27 मार्च

टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इकाई सहित यात्री वाहन कारोबार को स्लम्प सेल के जरिये एक अलग सहायक कंपनी बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने आज स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में यह खुलासा किया। कंपनी ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभप्रद रणनीतिक गठजोड़ बनाना है ताकि उत्पादों, आर्किटेक्चर, पावर ट्रेन, नई प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। स्लम्प सेल का मतलब यह हुआ कि यात्री वाहन कारोबार को मौजूदा कारोबार का कोई भी ऋण हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

इससे कारोबार की कमान में भी बदलाव दिख सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार के अध्यक्ष शैलेश चंद्र को इलेक्ट्रिक वाहन सहित कंपनी के यात्री कारोबार के अध्यक्ष मयंक पारीक की जगह नियुक्त किया जाएगा। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगी। पारीक कंपनी में अपना छह साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी 2021 फरवरी के अंत में सेवानिवृत हो जाएंगे। चंद्र और पारीक अगले कुछ सप्ताह में इस बदलाव पर काम शुरू करेंगे।

कंपनी ने एक बयान में कहा है, 'टीएमएल (टाटा मोटर्स लिमिटेड) बोर्ड ने कंपनी के यात्री वाहन कारोबार (इलेक्ट्रिक वाहन सहित) से संबंधित संपत्तियों, आईपी और कर्मचारियों के हस्तांरण के जरिये उसे एक सहायक कंपनी बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।' ये सभी बदलाव नियामकों, लेनदारों और शेयरधारकों की मंजूरियों पर निर्भर करेंगे और यह प्रक्रिया एक साल में पूरी होने की संभावना है।

टाटा मोटर्स का यात्री वाहन कारोबार वित्तीय प्रदर्शन के मोर्चे पर पिछले कई वर्षों से कंपनी पर एक दबाव बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में इसने 500 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा दर्ज किया। रिलायंस सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष मितुल शाह ने कहा, 'यह रणनीतिक दृष्टिकोण से एक साहसिक और सकारात्मक कदम है और उन्हें इससे यात्री वाहन कारोबार के लिए एक साथी पाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे उन्हें अपने वाणिज्यिक एवं यात्री वाहन कारोबार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।'

पिछले कुछ वर्षों के दौरान टाटा मोटर्स के यात्री वाहन कारोबार में काफी बदलाव दर्ज किया गया है। कंपनी ने टियागो, टिगोर, नेक्सन, हेक्सा, हैरियर और हाल में अल्ट्रोज़ एवं नेक्सन ईवी जैसे कई सफल मॉडलों के जरिये बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की है। हालांकि इंपैक्ट 2.0 डिजाइन दर्शन पर आधारित पूरी तरह से नई बीएस6 वाहन तैयार कर कंपनी अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाया है लेकिन कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण आगे उसकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

बैंकरों को उम्मीद

पैकेज से उद्योग को मिलेगी मदद

लॉकडाउन से कई फैक्टरी और सेवाएं बंद होने के कगार पर है, आरबीआई के कदम से मिलेगा सहारा

सोमेश झा और अभिजित लेले
नई दिल्ली/मुंबई, 27 मार्च

क्या वित्तीय क्षेत्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के राहत पैकेज से ऋण वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी?

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी राजकिरण राय जी. ने कहा, 'अभी जिंदा रहना सबसे महत्वपूर्ण है।'

राय को भरोसा है कि उद्योग से ऋण के लिए मांग बरकरार रहेगी, हालांकि ऐसा उत्पादक निवेश के लिए नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, 'लॉकडाउन की वजह से उत्पादन बंद हो गया है जिससे कंपनियां नकदी को लेकर सतर्क हैं। कंपनियां अपने खर्च (जैसे, अपने श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान) को पूरा करने के लिए उधारी पर निर्भर रहेंगी। लेकिन बड़े निवेश के बजाय व्यवसाय को बचाए रखना ज्यादा जरूरी होगा।'

यूनियन बैंक के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि आरबीआई के पैकेज से ऐसे समय में उद्योग के व्यवसाय को मजबूत बनाए रखने में मदद मिलेगी जब सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। इस लॉकडाउन की वजह से कई फैक्टरी इकाइयां और सेवाएं बंद होने के कगार पर हैं।

कर्ज और क्रेडिट कार्ड बकाया वसूली पर रोक से बैंकों के नकदी प्रवाह पर पड़ेगा असर

आरबीआई ने बैंकों को कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी चक्र के पुनर्मूल्यांकन की भी अनुमति दी है जिससे कि उन्हें लॉकडाउन की अवधि के दौरान फंसे कर्ज के तौर पर श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सके।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मुख्य कार्याधिकारी सुनील मेहता का मानना है कि हालांकि कोरोनावायरस के प्रभाव की वजह से ऋण उठाव में नरमी आएगी, लेकिन विभिन्न कारणों से उद्योग की ओर से पर्याप्त ऋण मांग रहेगी। मेहता ने कहा, 'कार्यशील पूंजी चक्र को बढ़ाया जाएगा। बैंक कार्यशील पूंजी का पुन: आकलन कर सकते हैं और इसे पुनर्गठन या डाउनग्रेड के तौर पर नहीं समझा जाएगा। इससे कोष की मांग बढ़ेगी और बैंकों के पास वृद्धि को रफ्तार देने के लिए अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। कोष की लागत निश्चित तौर पर नीचे आएगी।'

कुछ बैंकरों का कहना है कि आरबीआई का हस्तक्षेप आपूर्ति संबंधित समस्याओं का समाधान निकालेगा। सिंडिकेट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी मृत्युंजय महापात्र ने कहा, 'लेकिन मांग बाजार हालात पर निर्भर करेगी, जिसमें स्वयं ही बड़ा सुधार आएगा। फिलहाल, आरबीआई ने मांग बढ़ाने के लिए पर्याप्त राहत प्रदान की है।'

शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि कार्यशील पूंजी मांग में तेजी आने की संभावना है। कुमार ने कहा, 'लॉकडाउन के बाद नकदी प्रवाह प्रभावित हुआ है और व्यवसाय अपने परिचालन के वित्त पोषण के लिए बैंकों पर निर्भर करेंगे। आने वाले दिनों में निवेश गतिविधि में तेजी आएगी।'

लेकिन सभी ऋणों और क्रेडिट कार्ड बकाया के भुगतान पर अगले तीन महीने की रोक की वजह से बैंकों को नकदी प्रवाह से संबंधित कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा।

महापात्र ने कहा, 'नकदी प्रवाह से संबंधित कुछ समस्याएं सामने आएंगी। सिंडिकेट बैंक को बैंक ऋण ब्याज और किस्त के तौर पर हर साल 20,000 करोड़ रुपये मिलते हैं, इसलिए 5,000 करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह प्रभावित हो सकता है। लेकिन इस संबंध में पर्याप्त नकदी होगी, जैसा कि आरबीआई ने अन्य राहत उपाय में किया है।'

उम्मीद बढ़ी

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भरोसा है कि उद्योग की ऋण मांग बरकरार रहेगी
- लॉकडाउन की वजह से उत्पादन बंद हो गया है जिससे कंपनियां नकदी को लेकर सतर्क हैं
- कंपनियां अपने खर्च को पूरा करने के लिए उधारी पर निर्भर रहेंगी
- कुछ बैंकरों का कहना है कि आरबीआई का हस्तक्षेप आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालेगा

उद्योग की प्रतिक्रिया

नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 100 आधार अंक तक की कटौती, और रीपो दर घटने से बैंकों पर और अधिक कर्ज देने का दबाव आएगा।

वेणु श्रीनिवासन, चेयरमैन, टीवीएस

आरबीआई ने आर्थिक चुनौतियों और कोविड-19 संकट के दौर में जारी मौजूदा अनिश्चितता से निपटने के लिए यह कदम उठाया है।

सिरिल श्रॉफ
मैनेजिंग पार्टनर, सिरिल अमरचंद मंगलदास

आरबीआई का कदम निर्णायक है और वित्तीय बाजारों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए पैकेज से उधारी लागत घट गई है, क्योंकि देशभर में मौजूद व्यवसाय बंद हैं और अर्थव्यवस्था में मंदी के रुझान दिख रहे हैं।

गौतम हरि सिंघानिया, सीएमडी, रेमंड

सभी ऋण भुगतान को तीन महीने टाले जाने और रीपो तथा रिवर्स रीपो दरें घटाने का आरबीआई का कदम स्वागत योग्य है। इस तरह की राहत से निश्चित तौर पर कोविड-19 से प्रभावित हुए कामकाजी वर्ग और व्यवसायों को मदद मिलेगी।

नवीन जिंदल, चेयरमैन, जेएसपीएल

आरबीआई के उपायों से मौजूदा चुनौतीपूर्ण और अप्रत्याशित हालात से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। आरबीआई का दृष्टिकोण कोविड-19 से मुकाबले के लिए सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

वी एस पार्थसारथि
समूह सीएफओ, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा

ईएमआई टली

बैंकों की आय पर दबाव के आसार: सेन

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 27 मार्च

पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में कहा, 'मेरी राय में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा कदम उठाया है।'

जहां तक ईएमआई का सवाल है, आप 31 मार्च को घड़ी रोक रहे हैं। इसका मतलब है कि यह घड़ी पुन: शुरू होने तक (मान लीजिए कि 1 अगस्त तक) ईएमआई नहीं चुकाने की जरूरत होगी। अब यह सोचने की जरूरत होगी कि बैंकों की राजस्व स्थिति कैसी रहेगी। उनकी बैलेंस शीट में सब कुछ ठीक-ठाक होगा। हालांकि बैंकों को अपनी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें जमाकर्ताओं को ब्याज चुकाना होगा। इसका मतलब है कि बैंक इन महीनों के लिए कमजोर आय की समस्या से जूझने वाले हैं। इससे उनके कैपिटल टु रिस्क (वेटेड) ऐसेट्स रेशियो (सीआरएआर) में कमी आएगी। यदि सीआरएआर सख्त होता है तो इससे बैंक और ज्यादा ऋणों के संदर्भ में सख्ती बरतेंगे। इसलिए नए ऋण नहीं दिए जाएंगे। आरबीआई ने कहा है कि सीआरएआर मानक इस अवधि में लागू नहीं होंगे। हालांकि पूंजी आधार को अंत में फिर से खड़ा करने की जरूरत होगी। यह कैसे किया जाएगा, अभी इस बारे में बात नहीं की गई है। मेरा मानना है कि देर-सवेर सरकार को कदम उठाने होंगे, आरबीआई को नहीं। आरबीआई हालात के प्रबंधन के लिए सिर्फ नकदी मुहैया करा सकता है, लेकिन वह बैंकों को पूंजीकृत नहीं कर सकता।

- सरकार को बैंकों को पुन:पूंजीकृत कराने की जरूरत पर ध्यान देना होगा
- हालांकि बैंकों को अपनी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें जमाकर्ताओं को ब्याज चुकाना होगा

मौजूदा समय में, मांग कोई समस्या नहीं है। दरअसल, मौजूदा समय में समस्या आपूर्ति को लेकर है। कम से कम 55 प्रतिशत अर्थव्यवस्था ने अब उत्पादन रोक दिया है। इस तरह की स्थिति में मांग बढ़ाना एक खराब आइडिया है।

अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आपको चीजों को बहुत जल्द या देर से कर सकते हैं, आप स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

फर्मों के लिए लाभकारी

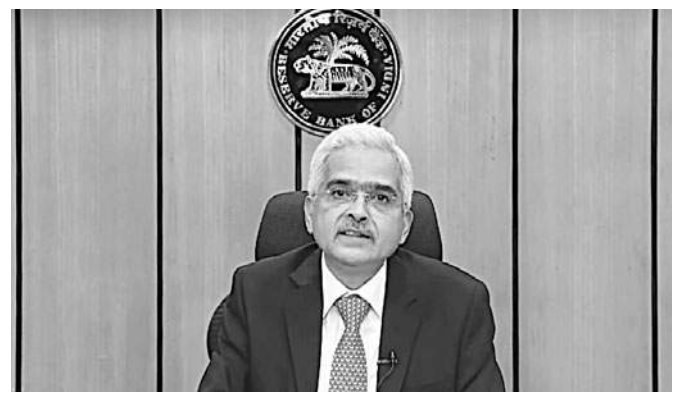
आरबीआई के कदम से कंपनियों को मिलेगी मदद

नकदी बढ़ने से फर्मों को मिलेगी राहत

बीएस संवाददाता
मुंबई, 27 मार्च

कोरोनावायरस महामारी के असर को कम करने के लिए ब्याज भुगतान पर छह महीने की रोक की मांग कर रही देश की कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से राहत की खबर मिली है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में 3.7 लाख करोड़ रुपये की नकदी बढ़ाने के साथ ही 1 मार्च, 2020 तक सभी बकाया दीर्घावधि ऋणों (टर्म लोन) की किस्त को तीन महीने तक चुकाने से छूट देने की घोषणा भी की है। टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने कहा कि आरबीआई के कदमों से बैंकों और एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) को फंसे कर्जों की पहचान करने के लिए वक्त मिलेगा और रीपो दरों और एसएलआर में कटौती की गुंजाइश बनेगी।

उनका कहना है, 'नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 1 फीसदी और रेपो रेट में कमी से बैंकों पर दबाव बनाया है कि वे ज्यादा कर्ज दें। आरबीआई ने फंसे कर्जों की पहचान के लिए वक्त देकर अच्छा कदम उठाया है नहीं तो इससे एक विशाल वित्तीय संकट की स्थिति बन जाती है और अगले दो महीनों में कई ग्राहकों के लिए मासिक किस्त (ईएमआई) का भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा।'

सिरिल अमरचंद मंगलदास के सिरिल श्रॉफ ने कहा, 'आरबीआई ने कोविड-19 के गहराते संकट की वजह से आर्थिक संकट और अनिश्चितता जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक कदम उठाया है। आरबीआई ने तेजी से और निर्णायक ढंग से काम करते हुए आर्थिक तंत्र में नकदी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इससे बैंकों को आपातकालीन कोविड क्रेडिट लाइनें शुरू करने या जारी रखने में मदद मिलेगी।'

आरबीआई के इन उपायों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की उन कंपनियों को मदद मिलेगी जो अपने कारोबार में अचानक गिरावट का सामना कर रही हैं। एस्सार पोर्ट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) राजीव अग्रवाल कहते हैं, 'सीआरआर में कटौती के साथ ब्याज तथा मूल राशि के भुगतान में तीन महीने की रोक से नकदी बढ़ाने में आसानी होगी और इससे उद्योग के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी। लेकिन कोविड-19 की वजह से बने आर्थिक संकट जैसी स्थिति से उबरने के लिए सरकार को जरूरी प्रोत्साहन पैकेज देना होगा जिसके लिए और अधिक कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है।'

पहले से ही अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को तीन महीने के लिए ब्याज भुगतान पर रोक से कुछ राहत मिलेगी।

जेएलएल के सीईओ और कंट्री हेड रमेश नायर ने कहा, 'रीपो दर में कटौती ने 2009 के स्तर को भी पार कर लिया है जब अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित हुई थी और नीतिगत दर कम होकर 4.75 फीसदी हो गई थी। यह कदम कोविड-19 के प्रभाव को कम करते हुए वृद्धि बढ़ोतरी को सुनिश्चित करने और महंगाई को नियंत्रित के लिए है।' वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) से रियल एस्टेट डेवलपरों का कुल बकाया कर्ज मार्च 2020 तक लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ठीक इसी वक्त में मासिक किस्त भुगतान में छूट से निश्चित रूप से घर खरीदने वालों को लाभ होगा क्योंकि इन वित्तीय संस्थानों ने मार्च 2020 तक अनुमानत: 20 लाख करोड़ रुपये उधार दिए हैं। एचएफसी को प्रतिमाह लगभग 60,000 करोड़ रुपये ईएमआई मिलती है।

- वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और आवासीय वित्त कंपनियों से रियल एस्टेट डेवलपरों का कुल बकाया कर्ज मार्च 2020 तक लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है
- ठीक इसी वक्त में मासिक किस्त भुगतान में छूट से निश्चित रूप से घर खरीदने वालों को लाभ होगा

रियल्टी की मांग और नकदी में सुधार की उम्मीद

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 27 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की घोषणा से हाउसिंग की मांग बढ़ेगी और रियल एस्टेट कंपनियों की नकदी में सुधार आएगा। यह कहना है प्रॉपर्टी डेवलपरों और कंसल्टेंटों का। मुंबई की सनटेक रियल्टी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कमल खेतान ने कहा, रीपो दरों में 75 आधार अंक की कटौती से कर्ज के जरिए घर खरीदने वाले नए खरीदारों की मांग में मजबूती आएगी। होम लोन समेत सावधि कर्ज पर तीन महीने की मोहलत भी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए राहत लाएगा और वे परिचालन की जरूरत पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी और अपनी कारोबारी रणनीति को फिर से दुरुस्त कर पाएंगी।

टाटा रियल्टी ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजय दत्त ने कहा, नई घोषणा से घर खरीदारों की अवधारणा में सुधार लाने में भी दिद मिलेगी, साथ ही मध्यम व अफोर्डेबल हाउसिंग के मांग का चक्र दोबारा बहाल होगा।

उन्होंने कहा, अनिश्चिता के इस दौर में शेयर बाजार में काफी उतारचढ़ाव दिख रहा है, ऐसे में हमारा अनुमान है कि कई लोग प्रॉपर्टी में निवेश पर विचार करेंगे क्योंकि यह ज्यादा स्थिर और लंबी अवधि की परिसंपत्ति है।

मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घरों की बिक्री और नई पेशकश में 42-42 फीसदी की कमी आई है

रियल एस्टेट डेवलपर पिछले कुछ वर्षों से कम बिक्री और सख्त नकदी का सामना कर रहे हैं। सितंबर 2018 के बाद से एनबीएफसी के नकदी संकट से डेवलपरों की पुनर्वित्त सुविधा को झटका लगा है।

बेंगलूरु की पूर्वांकरा के प्रबंध निदेशक आशिष आर पूर्वांकरा ने कहा, पंजीकरण न होने और नई पेशकश पर स्पष्टता न होने से दरों में कटौती का फायदा नकदी प्रवाह के प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर आवंटन में मिलेगा, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा।

एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घरों की बिक्री और नई पेशकश में 42-42 फीसदी की कमी आई है।

एनबीएफसी

कर्ज चुकाने पर ध्यान देंगी एनबीएफसी

बॉन्ड बाजार आवास वित्त कंपनियों व एनबीएफसी के लिए रकम जुटाने का अहम स्रोत

श्रीपाद ऑटे और सुब्रत पांडा
मुंबई, 27 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नकदी प्रवाह बढ़ाए जाने के उपायों से नकदी किल्लत झेल रहे बैंकिंग क्षेत्र को काफी राहत मिलेगी क्योंकि इसके कुछ हिस्से का उपयोग ऋणदाताओं द्वारा अपनी ऋण देनदारी की अदायगी की जाएगी। ऐसे समय में जब सावधि ऋण के पुनर्भुगतान में मोहलत दिए जाने से नकदी प्रवाह पर दबाव बढ़ सकता था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नीतिगत उपायों के जरिये प्रणाली में पर्याप्त नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने की कोशिश की है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह रीपो से जुड़ी दर पर 1 लाख करोड़ रुपये के लिए 3 वर्षों की लक्षित टर्म रीपो के लिए नीलामी आयोजित करेगा। इसके अलावा नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) में छूट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत सुविधा बढ़ाए जाने से प्रणाली में प्रत्येक से 1.37 लाख करोड़ रुपये प्रवाहित होंगे।

इन तीनों उपायों से कुल मिलाकर प्रणाली में 3.74 लाख करोड़ रुपये प्रवाहित होंगे।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों द्वारा लंबी अवधि के रीपो स्कीम के तहत ली जाने वाली रकम को निवेश ग्रेड के बॉन्डों, वाणिज्यिक और गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों में लगाई जाएगी।

कॉरपोरेट बॉन्ड का एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 60 फीसदी हिस्सा एनबीएफसी द्वारा जारी होता है

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक कृष्णन सीतारमण ने कहा, 'निकट भविष्य में कई एनबीएफसी के पास नकदी प्रवाह की समस्या होगी क्योंकि उनके सामान्य संग्रह प्रभावित होंगे। जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक एनबीएफसी के ऋण वितरण पर काफी असर रहेगा और उनका संग्रह भी कम होगा। लेकिन किराया, वेतन, ऋण बाजार की अदायगी आदि स्थायी खर्च को उन्हें निपटाना होगा।'

कॉरपोरेट बॉन्ड का एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 60 फीसदी हिस्सा एनबीएफसी द्वारा जारी होता है। इंडिया रेटिंग्स के प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र की रेटिंग) प्रकाश अग्रवाल ने कहा, 'बॉन्ड बाजार आवास वित्त कंपनियों सहित एनबीएफसी के लिए रकम जुटाने का एक प्रमुख स्रोत है। अब तक बॉन्ड बाजार द्वारा अदायगी के लिए कोई मोहलत नहीं दी गई है। इसलिए हमारा मानना है कि एनबीएफसी द्वारा अतिरिक्त बैंक उधारी का उपयोग वे अपने बॉन्ड बाजार की देनदारी को चुकाने में करेंगी।'

एनबीएफसी (और सभी ऋणदाताओं) को सावधि ऋण पर मोहलत दिए जाने की उम्मीद है क्योंकि इससे वित्तीय कंपनियों को पूंजी अथवा बॉन्ड बाजार की अपनी देनदारी को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही नकदी संकट से जूझ रहा है।

बैंक उधारी के अलावा लॉन्ग टर्म रीपो ऑपरेशन (एलटीआरओ) भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इक्रा के प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र की रेटिंग) अनिल गुप्ता ने कहा, 'एलटीआरओ के जरिये रकम बैंकों के नकदी प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि यह आरबीआई से एक नए वित्तपोषण के रूप में आ रहा है और इसकी लागत भी कम है।'

नकदी प्रवाह में सख्ती, कम जोखिम के कारण बॉन्ड प्रतिफल में काफी बढ़ोतरी हुई। गुप्ता ने कहा कि एनबीएफसी को मिलने वाली इस रकम से प्रतिफल को सामान्य स्तर पर लाने में मदद मिलेगी।

इस प्रकार इस एलटीआरओ को मिलने वाली प्रक्रिया काफी अहम होगी। कुछ उद्योग विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अपने ग्राहकों को मोहलत देने वाले एनबीएफसी बैंकों द्वारा एनबीएफसी दी गई मोहलत पर निर्भर होंगी।

मौजूदा परिस्थितियों में एनबीएफसी और एचएफसी के ऋण वितरण में वृद्धि की संभावना नहीं है लेकिन लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के बाद समग्र मांग में तेजी आने की उमीद है।

संक्षेप में

टीएचडीसी, नीपको बेचकर सरकार ने जुटाया धन

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दो बिजली कंपनियों टीएचडीसी और नीपको में अपनी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के जरिए 11,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह रणनीतिक बिक्री एनटीपीसी को की गई है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। दीपम सचिव ने एक ट्वीट में कहा, दीपम ने दो और रणनीतिक विनिवेश सौदों को पूरा कर लिया है। सरकार ने एनटीपीसी को टीएचडीसी की 74.49 प्रतिशत हिस्सेदारी 7,500 करोड़ रुपये में और नीपको की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी 4,000 करोड़ रुपये में बेची है। इन दोनों बिक्री से सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक विनिवेश से 46,500 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। *भाषा*

केंद्र ने जारी किया मनरेगा का 4,431 करोड़ बकाया

केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के बकाये के भुगतान के लिए 4,431 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि 10 अप्रैल तक सभी बकाये का भुगतान कर दिया जाएगा। एक दिन पहले सरकार ने इस योजना के तहत मजदूरी में वृद्धि की थी। यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब देशव्यापी लॉकआउट के कारण श्रमिकों के पास कोई काम नहीं बचा है। *भाषा*

देशबंदी से एचयूएल, आईटीसी व अन्य पर असर

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 27 मार्च

देशबंदी के दौरान परिचालन को लेकर स्पष्टता न होने और कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) जैसे एचयूएल, आईटीसी का परिचालन बाधित हुआ है और जरूरी सामानों के सीमित विनिर्माण के कारण फैक्टरियां बंदी की ओर हैं।

एचयूएल और आईटीसी दोनों ने आज कहा कि उनका परिचालन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हुए लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ है। ऐसी ही स्थिति मैरिको, नेस्ले, डाबर इमामी और अन्य की भी है। बीएसई में दी गई जानकारी में एचयूएल ने कहा है कि कोरोनावायरस को रोकने के लिए 21 दिन की देशबंदी के दौरान कंपनी की विनिर्माण, वितरण केंद्र, गोदामों और विस्तारित आपूर्ति श्रृंखला पर विपरीत असर पड़ा है।

एचयूएल ने कहा है, 'हमने अपने ज्यादातर परिचालन स्थलों पर काम घटा दिया है और परिचालन रद्द कर दिया है।' सूत्रों ने कहा कि कुछ स्थलों पर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है।

यही स्थिति नेस्ले और मैरिको की है, जिन्होंने अपना परिचालन कम या लंबित कर दिया है।

आईटीसी ने सिगरेट विनिर्माण का काम रोक दिया है, जो उसके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। आईटीसी ने जरूरी सामान जैसे आटा, नूडल्स, बिस्कुट, स्नैक्स, साबुन, सैनिटाइजर और अन्य उत्पादों का उत्पादन जारी रखने का फैसला किया है। यह काम भी कम कर्मचारी होने की वजह से सुस्त रफ्तार से हो रहा है।

आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण के अलावा आईटीसी ने देश भर के विभिन्न इलाकों में स्थित अपनी फैक्टरियों में परिचालन रोक दिया है।

आईटीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, 'कुछ राज्यों में हमें आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण और जरूरी उत्पादों की ढुलाई के लिए के लिए अनुमति मिली है। फैक्टरियों, गोदामों से वितरण केंद्रों तक माल की आवाजाही हो रही है। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में और स्थानीय स्तर पर भी ट्रकों की आवाजाही प्रभावित हुई है और इसे इसे सामान्य होने में कुछ दिन लगेंगे। पूरी प्रक्रिया आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के तहत आता है।'

डाबर ने भी अपना परिचालन कई विनिर्माण इकाइयों में रोक दिया है और सिर्फ जरूरी सामान जैसे आयुर्वेदिक दवाएं, च्यवनप्राश, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वाश और अन्य सामान बनाए जाते हैं।

उद्योग के एक अधिकारी कहा कि जहां कं पनियां फैक्टरियों में न्यूनतम कर्मचारी रखने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की कवायद कर रही हैं, वहीं उसे विनिर्माण व वितरण प्रक्रिया के हर स्तर पर मानव संसाधन की कमी से जूझना पड़ रहा है।

एक अधिकारी ने कहा, 'विभिन्न राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन से और ज्यादा स्पष्ट रुख और सहयोग की जरूरत है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की बाधारहित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। कुछ स्थानीय प्रशासन की ओर से स्थिति साफ की गई है और कुछ इलाकों में पास जारी किए गए हैं, वहीं देश भर में ऐसा नहीं हो सका है। इसकी वजह से आपूर्ति व वितरण श्रृंखला प्रभावित हो रही है।'

मैरिको ने कहा है कि उसके वितरण नेटवर्क पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है।

उद्योग के अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में और राज्यों के भीतर ट्रकों की बाधारहित आवाजाही कंपनियों के लिए बड़ा मसला है। इसकी वजह से वितरण प्रभावित हो रहा है और अंतिम छोर तक माल पहुंचाने का मसला बना हुआ है। खुदरा स्तर पर किसी तरह की अफरातफरी की स्थिति से बचने के लिए आवाजाही के मसले का समाधान करना होगा।

उद्योग के एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'वस्तुओं व कर्मचारियों की आवाजाही के लिए कुछ स्थानीय प्रशासन से तालमेल हुआ है, जिसमें पास जारी किया जाना शालिम है। लेकिन प्राधिकारियों को इस मसले पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।'

एचयूएल और आईटीसी सहित अन्य एफएमसीजी कंपनियों ने कहा कि वे कुछ सरकारी प्राधिकारियों के साथ काम कर रही हैं, जिससे कि विनिर्माण व वितरण का काम जारी रखा जा सके।

आईटीसी के प्रवक्ता ने कहा, 'हम राज्य के प्राधिकारियों व स्थानीय प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं, जिससे विनिर्माण व वितरण गतिविधियां सुनिश्चित हो सकें और कम से कम कर्मचारियों के सहयोग से बाधारहित काम जारी रह सके।'

तमाम राज्य फैक्टरी कर्मचारियों और वितरण नेटवर्क में लगे लोगों व ई कॉमर्स कारोबारियों के लिए पास जारी कर रहे हैं।

प्रभावित हो रहा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन व वितरण

- सभी एफएमसीजी कंपनियों ने या तो विनिर्माण बंद किया है या अपने संयंत्रों में उत्पादन कम कर दिया है
- कर्मचारियों व ट्रकों की उपलब्धता और आवाजाही उत्पादन व वितरण प्रभावित करने की प्रमुख वजह
- आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है
- सरकारों व स्थानीय प्रशासन से और ज्यादा स्पस्टता और समर्थन चाहती हैं एफएमसीजी कंपनियां
- कंपनियां विभिन्न राज्य सरकारों से बात कर रही हैं, जिससे बंद फैक्टरियों में परिचालन बहाल किया जा सके

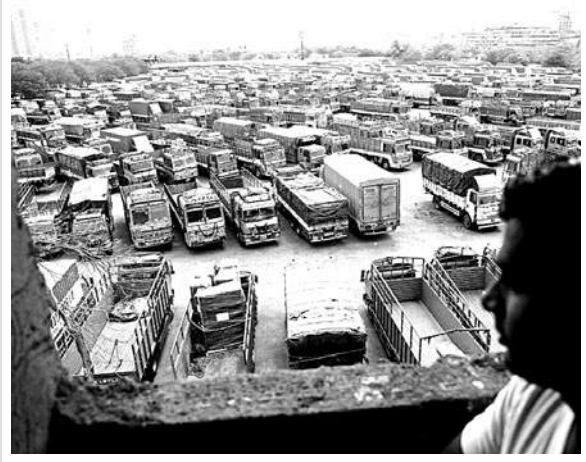

आवाजाही बाधित होने का एफएमसीजी कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। शुक्रवार को लॉकडाउन के तीसरे दिन नवी मुंबई में एपीएमसी ट्रक टर्मिनल में खड़े ट्रक *फोटो-पीटीआई*

3 दशक के निचले स्तर पर जा सकती है वृद्धि दर

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 27 मार्च

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विज ने आज कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। यह करीब 3 दशक के का सबसे निचला स्तर होगा। मूडीज ने इसके पहले 5.3 प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया था। वैश्विक आपदा कोरोनावायरस के आर्थिक स्तर देखते हुए एजेंसी ने अनुमान घटाया है।

मूडीज ने कहा है कि 2020 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर और आमदनी में तेज गिरावट का अनुमान है। इससे आगे घरेलू मांग और 2021 में रिकवरी कम होने की संभावना है। इसने कहा है, 'बैंक व गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों में नकदी की कमी की वजह से भारत में पहले से ही कर्ज के प्रवाह का संकट बना हुआ है।'

अगर मूडीज का अनुमान सही निकलता है तो चीन, जहां से कोरोनावायरस फैला है, 2020 में वृद्धि दर के हिसाब से भारत से आगे निकल जाएगा, जिसकी वृद्धि दर चालू कैलेंडर साल में 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही चीन की वृद्धि दर 2021 में भी भारत से ज्यादा होगी। अगले साल चीन की वृद्धि दर 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि भारत की वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

इसके पहले 1991-92 में भारत की वृद्धि दर 1.1 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

आधिकारिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में 5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, इसके लिए 2019-20 की चौथी तिमाही में 4.7 प्रतिशत वृद्धि दर की जरूरत होगी, जो मुश्किल नजर आती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी शुक्रवार को कहा है कि 2019-20 की चौथी तिमाही में वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत रहने को लेकर जोखिम है। मूडीज ने पिछले 40 दिन के दौरान तीन बार भारत की वृद्धि दर के अनुमान में कमी की है। इससे पता चलता है कि कोरोनावायरस के कारण बदलती स्थिति में वृद्धि को लेकर कितने उतार चढ़ाव की स्थिति है। जी-20 देशों के लिए मूडीज ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान 0.5 प्रतिशत कम कर दिया है। पहले 2.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।

वित्त वर्ष 2020 में 10 विकसित देशों में से 8 की वृद्धि दर में गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जबकि एक देश की वृद्धि दर यथावत रहने का अनुमान है। मूडीज के मुताबिक सिर्फ दक्षिण कोरिया की की अर्थव्यवस्था 0.1 प्रतिशत बढ़ेगी। वहीं चालू कैलेंडर वर्ष में दूसरी ओर 10 उभरते बाजारों में 5 की जीडीपी वृद्धि में गिरावट का अनुमान है।

- मूडीज के मुताबिक कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रह सकती है
- अगर ऐसा हुआ तो यह 1991-92 की 1.1 प्रतिशत वृद्धि दर के बाद सबसे निचला स्तर होगा
- ऐसा होने पर चीन की वृद्धि दर 2020 में भारत की तुलना में ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है
- जी-20 देशों के लिए मूडीज ने वृद्धि अनुमान 0.5 प्रतिशत घटाया है

2020-21 में महज 2 प्रतिशत रहेगी वृद्धि दर

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए व्यापक कदमों के बावजूद घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अप्रैल-जून 2020 तिमाही में शून्य से 4.5 प्रतिशत नीचे जा सकती है।

वहीं एजेंसी ने यह भी कहा है कि कोरोनावायरस के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर सिर्फ 2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

इक्रा ने शुक्रवार को कहा, 'रिजर्व बैंक की ओर से अभी घोषित कदमों के बावजूद हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि ऋणात्मक 4.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 21 के दौरान वृद्धि दर 2 प्रतिशत रह सकती है।' एजेंसी ने कहा कि कोरोनावायरस का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है और भारत और विश्व में आर्थिक गतिविधियों पर अनिश्चितता का असर पड़ रहा है। एजेंसी ने रिजर्व बैंक के नीतिगत कदमों का स्वागत किया है और कहा है कि यह समग्र घोषणाओं का एक समूह है। *एजेंसियां*

कीटाणुनाशक वाइप्स और मास्क बनाने में जुटी वेलस्पन

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 27 मार्च

देश में कोरोनावायरस (कोविड-19) संक्रमण फैलने के बीच, वेलस्पन समूह कीटाणुनाशक वाइप्स और मास्क का निर्माण करने के लिए गुजरात के अंजार में अपनी कपड़ा फैक्टरियों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि निजी सुरक्षा के लिए मांग और आपूर्ति का अंतर पूरा किया जा सके।

वेलस्पन समूह के अध्यक्ष बीके गोयनका ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि कंपनी ने आने वाले हफ्तों में सैकड़ों हजार मास्क और वाइप्स तैयार करने की योजना बनाई है जो गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी जमीनी कामगारों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।

इस संयंत्र में घरेलू बाजार के साथ-साथ ज्यादातर निर्यात के लिए होम टेक्सटाइल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इस संयंत्र में वाहन, सुरक्षात्मक, घर की साज-सज्जा से जुड़े कपड़े के लिए तकनीकी टिकाऊ कपड़े तैयार किए जाने के अलावा इस्तेमाल करके फेंके जाने वाले वाइप्स, घाव पर लगाने वाली पट्टी, डायपर, पर्दे और गाउन जैसे उत्पादों के लिए तकनीकी टेक्सटाइल क्षमताएं भी हैं। अब समूह इसमें स्वाभाविक विस्तार देते हुए देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कीटाणुनाशक वाइप्स और मास्क का निर्माण करने की संभावानाएं देख रहा है।

गोयनका कहते हैं, 'जब भी बड़े पैमाने पर सरकारी पहलों और समाज का समर्थन करने की बात आती है तब वेलस्पन समूह हमेशा इसमें आगे रहा है। कारोबारी नजरिये से भी देखा जाए तो गैर-बुने उत्पाद तैयार करने के साथ-साथ सुरक्षात्मक कपड़ों, फिल्टरेशन, व्यक्तिगत साफ-सफाई और कॉस्मेटिक श्रेणी के अलग ऐप्लिकेशन के लिए वाइप्स तैयार करना हमारे लिए एक स्वाभाविक विस्तार है।'

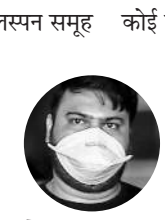

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस

उन्होंने कहा कि कंपनी का मकसद देश में व्यक्तिगत सुरक्षा और वाइप्स के मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना है।

हालांकि समूह ऐसी तकनीक और कौशल का इस्तेमाल कर रहा है जो इस तरह के तैयार उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं है। समूह का मानना है कि आने वाले हफ्तों में यह कुछ सैंकड़ों हजार मास्क और हैंड वाइप्स तैयार करने की योजना तैयार कर सकता है।

गोयनका कहते हैं, 'हालांकि, मौजूदा लॉकडाउन की वजह से प्रमुख सामग्री जुटाने और कार्यबल का प्रबंधन करने में अपनी ही चुनौतियां हैं। इसके लिए हम सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ काम कर रहे हैं जो विनिर्माण प्रक्रिया में कोई बाधा न आए इसके लिए अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं।'

फिलहाल मुख्य प्राथमिकता जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए रफ्तार से उत्पादन बढ़ाना। वेलस्पन का पूरा जोर इस तरह के मास्क और कीटाणुनाशक वाइप्स बनाने पर है जो सभी जमीनी कामगारों और उनके परिवारों के लिए होगा जो इस महामारी के बीच भी जरूरी सेवाएं देने के लिए जोखिम के बावजूद काम कर रहे हैं।

वैश्विक स्तर के बेड और बाथ लिनन तैयार करने वाली दिग्गज कंपनियों में शामिल वेलस्पन भी कॉटन टेरी तौलिया, समुद्री तट पर इस्तेमाल होने वाले तौलिया, बाथ रग्स और मैट, नहाने के बाद पहनने वाले कपड़े, कॉटल शीट, तकिया, कम्फोर्टर जैसे सामान कंपनी के वापी और अंजार संयंत्र में तैयार किए जाते हैं।

कारोबार तेज

- मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कीटाणुनाशक वाइप्स और मास्क का निर्माण करने की संभावानाएं देख रहा वेलस्पन ग्रुप
- कंपनी ने आने वाले हफ्तों में सैंकड़ों हजार मास्क और वाइप्स तैयार करने की योजना बनाई
- कंपनी ने कहा कि गैर-बुने उत्पाद तैयार करने के साथ-साथ सुरक्षात्मक कपड़ों, फिल्टरेशन, व्यक्तिगत साफ-सफाई और कॉस्मेटिक श्रेणी के ऐप्लिकेशन के लिए वाइप्स तैयार करना हमारे लिए स्वाभाविक विस्तार

लॉकडाउन खत्म होने पर ही कटेगा टोल

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 27 मार्च

कोरोनावायरस से उपजे संकट के बीच देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। टोल संचालकों की टोल संग्रह समयावधि में इन दिनों की कुल संख्या के बराबर विस्तार दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े अनुबंधों पर फोर्स मेजर भी लागू कर दिए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक अधिकारी ने बताया, 'सभी परियोजनाओं के लिए फोर्स मेजर लागू कर दिए गए हैं और जहां तक टोल पर संग्रह बंद करने की बात है, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा।' ठेकेदारों तथा सरकार के बीच हुए रियायत समझौते के तहत टोलिंग अवधि के विस्तार की अनुमति है।

फोर्स मेजर ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में लाया जाता है जब किसी अनुबंध को पूरा करना संभव न हो। यह किसी प्राकृतिक या अपरिहार्य आपदा के चलते अनुबंध में दिए गए समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति की देनदारी को समाप्त करता है। अधिकारी ने बताया कि रियायत संबंधी सभी अनुबंधों में फोर्स मेजर का प्रावधान है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की है।

ध्यातव्य है कि नोटबंदी के समय भी कई सप्ताह तक टोल परिचालन बंद रहा था और उस समय भी टोल संग्रह समयावधि को इतने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने 500 रुपये तथा 1,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह को निलंबित करने की घोषणा की थी और इसके बाद 2 दिसंबर 2016 से दोबारा टोल व्यवस्था बहाल हुई थी।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च का मानना है कि कोविड-19 के विस्तार को रोकने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा बड़े शहरों में लगाए गए लॉकडाउन से वहां बुनियादी ढांचे निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी। इसके चलते लघु अवधि में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनियों की राजस्व वृद्धि प्रभावित होगी।

साथ ही, कामगार श्रमिकों की एक बड़ी संख्या अपने घरों की ओर लौट रही है और वे स्थिति सामान्य होने के बाद ही वापिस आएंगे। इसमें एक महीना या इससे ज्यादा समल लग सकता है।

इसके अलावा, राजस्व संग्रह भी प्रभावित होगा। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि इन सभी के साथ ओवरहेड्स तथा वित्तीय शुल्क के तौर पर होने वाले खर्च से भी निर्माण कंपनियों की लाभप्रदता प्रभावित होने की संभावना है। एमईपी इन्फ्रा के अध्यक्ष जयंत डी. महिस्कर कहते हैं, 'इस समय कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है। चीजें ठहर गई हैं और इन्हें दोबारा पटरी पर आने में 3-4 महीने का समय लग जाएगा।' वह कहते हैं, 'अगर लॉकडाउन हटा भी लिया गया तो भी काम शुरू होने में लंबा वक्त लगेगा क्योंकि एक ओर श्रमिक उपलब्ध नहीं होंगे तथा दूसरा विनिर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा।'

बंदी के कारण सड़कें सूनी पड़ गई हैं। कोलकाता में शुक्रवार को परिवहन सेवा न मिलने के कारण अपनी बच्ची को ट्रॉली बैग पर बिठाकर लौटता विस्थापित श्रमिक *-पीटीआई*

घरेलू इस्पात उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण समय

अदिति दिवेकर
मुंबई, 27 मार्च

कोविड-19 और 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही में घरेलू इस्पात विनिर्माताओं के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने आज यह जानकारी दी। एजेंसी का कहना है कि घरेलू कंपनियों को कमजोर मांग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे स्टॉक के जमावड़े में इजाफा और इस्पात के दामों पर दबाव बढ़ने के आसार हैं। हालांकि हाल के सप्ताहों में चीन में कोविड-19 के मामलों में कमी देखी गई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मार्च में दर्ज किए गए मामलों की संख्या में तेजी आई है। जब तक हालात में सुधार नहीं होता है, तब तक विदेशों की मांग नरम रहेगी।

इसके अलावा इक्रा को इस बात की उम्मीद नहीं दिख रही है कि वित्त वर्ष 21 के दौरान घरेलू इस्पात उपभोग वृद्धि में मजबूती आएगी। वित्त वर्ष 2020 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के मुकाबले वित्त वर्ष 2021 के दौरान पहली तिमाही काफी कमजोर रहने की बात को ध्यान में रखते हुए खपत की वृद्धि दर दो से तीन प्रतिशत के आस-पास रहने के आसार हैं। निर्यात बाजार भी ठंडा रहने के कारण तथा दूसरी छमाही के दौरान मांग की स्थिति में सुधार को देखते हुए अगले वित्त वर्ष में सालाना एक करोड़ टन की क्षमता विस्तार के कारण वित्त वर्ष 2021 में उद्योग का क्षमता उपभोग घटकर 79 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह 81 प्रतिशत था।

बीएस सूडोकू 3700 | परिणाम संख्या 3699

1	2				9		7	
	3	7			8			2
	9		2			5		3
					3			6
	4						1	
8								9
6	5						2	4
2		4		1		6		

4	9	8	1	7	5	2	3	6
6	2	5	3	9	8	4	7	1
7	3	1	6	2	4	9	8	5
1	5	6	9	4	3	7	2	8
9	7	3	8	5	2	6	1	4
8	4	2	7	6	1	5	9	3
2	8	7	4	1	6	3	5	9
5	1	4	2	3	9	8	6	7
3	6	9	5	8	7	1	4	2

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान
★☆☆☆☆

देश के प्रमुख शहरों में निर्माण गतिविधियां रुकीं

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 27 मार्च

देश भर में निर्माण गतिविधियां रुक गई हैं। अगले 3 से 4 महीने तक स्थिति में बदलाव की संभावना नहीं नजर आ रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि मुंबई महानगर क्षेत्र, दिल्ली, पुणे और बेंगलूरु जैसे प्रमुख केंद्रों पर निर्माण गतिविधियां रुक गई हैं और इनमें प्रगति उम्मीद से बहुत नीचे है। यह स्थिति अप्रैल में भी जारी रह सकती है।

एमईपी इन्फ्रा के चेयरमैन जयंत डी म्हाइस्कर ने कहा, 'जहां तक इस समय स्थिति का सवाल है, इस समय कुछ भी नहीं हो रहा है। चीजें स्थिर हो गई हैं और काम शुरू होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे।'

इंडिया रेटिंग ऐंड रिसर्च का मानना है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन किए जाने से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने में देरी होगी। इससे कम अवधि के हिसाब से निर्माण कंपनियों के राजस्व वृद्धि पर असर पड़ेगा।

लॉकडाउन वापस लिए जाने के बाद भी काम शुरू होने में काफी दिन लगेंगे, क्योंकि काम करने के लिए मजदूर नहीं होंगे और निर्माण साइट पर प्रतिबंध भी लगे होंगे।

इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है और 21 दिन के लॉकडाउन का दूसरा दिन है। निर्माण क्षेत्र के मजदूर बड़े पैमाने पर अपने घरों की ओर चले गए हैं और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले मजदूर तभी वापस आएंगे जब स्थिति सामान्य होगी। इसमें सब कुछ सही होने के बाद एक महीने और लग सकते हैं। इसकी वजह से राजस्व का अनुमान भी प्रभावित हो सकता है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक इसके साथ ही अन्य तमाम खर्च जारी रहने की वजह से भी निर्माण कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा, जो पहले से ही संकट से गुजर रही हैं।

रेटिंग एजेंसी ने निर्माण क्षेत्र की रेटिंग वित्त वर्ष 2021 के लिए स्थिर से ऋणात्मक कर दी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा कुछ खास कंपनियों का काम रोके जाने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है।

इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र से धन मिला भी चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता है। एजेंसी को आशंका है कि अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य में सुस्ती बनी रहेगी।

आर्थिक समीक्षा 2019-20 के मुताबिक सड़कों का निर्माण तेजी से बढ़ा है और 2015-16 के 17 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर यह 2018-29 में 29.7 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया। बहरहाल 2019-20 में रफ्तार सुस्त पड़ी है और सितंबर 19 तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन निर्माण 12.7 किलोमीटर रही है।

- परियोजनाओं की डिलिवरी का होगा और बुरा हाल
- विशेषज्ञों का कहना है कि अभी सब कुछ ठहर गया है और काम शुरू होने में कम से कम 3-4 महीने लगेंगे

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 31

खूबियां-खामियां उजागर

जब भी कोई संकट आता है तो व्यवस्था की खूबियां और खामियां उजागर होती हैं। सन 2016 में नोटबंदी के दौरान देश के रोजमर्रा के जीवन में मची अफरातफरी के बीच हमारी सामाजिक स्थिरता उजागर हुई थी। लोग बैंक शाखाओं पर कतार में लगे-लगे मर गए लेकिन कहीं दंगा नहीं हुआ। इसके ठीक विपरीत गत माह पूर्वोत्तर दिल्ली में भड़की हिंसा ने हमारी उस सामाजिक खामी को उजागर किया जो यदाकदा देखने को मिल जाती है। पुलिस शुरुआत में नियंत्रण पाने में नाकाम रही और इसने दिखाया कि कानून का प्रवर्तन करने वाली मशीनरी किस हद तक सांप्रदायिक है।

कोविड-19 ने नए सिरे से हमारी ताकत और कमियां उजागर की हैं। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की और शीर्ष से नेतृत्व संभाला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लोगों को बताया कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। परंतु संकट से ग्रस्त लोगों की मदद तथा आर्थिक मोर्चे पर उसके दुष्परिणामों से निपटने की राह राज्यों ने दिखाई है। यह आश्वस्त करने वाला दृश्य है कि भारत विभिन्न स्तरों पर मजबूत है। इसके अलावा मीडिया को भयभीत करने या उसके भोंपू बन जाने के तमाम प्रमाणों के बीच इस बात में भी ज्यादा संदेह नहीं कि प्रवासी कामगारों के पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों की ओर लौटने (क्योंकि सभी यात्री सेवाएं ठप हैं) की खबरों के बाद सरकारों ने उनके लिए भोजन व्यवस्था की और परिवहन का इंतजाम किया जा रहा है। आशा है कि लोग अपने घरों को जा सकेंगे या जहां हैं वहां रुक सकेंगे ताकि हालात सामान्य होने तक उन्हें आसपास कुछ काम-धंधा मिल सके।

जनधन खाते, आधार और मोबाइल की तिकड़ी जिसे 'जाम' का नाम दिया गया था, वह काम आई है। ऐसे वक्त में जब यह लगने लगा था कि आधार लोगों तक लाभ हस्तांतरित करने के तरीके के बजाय सरकार की निगरानी का उपाय अधिक है, इसने अपनी उपयोगिता साबित की है। वित्त मंत्री ने जिन उपायों की घोषणा की है उनमें से कई को पूरा करने में यह उपयोगी साबित होगा। बिना इन तीनों उपायों के नकद हस्तांतरण कर पाना अत्यधिक कठिन होता। व्यवस्था बेहतरीन नहीं है। यह सही है कि लोग प्रभावित हुए हैं लेकिन इस अपरिपक्वता के बावजूद यह काफी बेहतर है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

कुछ कमजोरियां भी उजागर हुई हैं। मसलन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारी कमी। यह बात दशकों से हमारे सामने है। टीकाकार लगातार इस पर टिप्पणी करते रहे हैं। दुनिया की कुछ हद तक विकसित तमाम अर्थव्यवस्थाओं के उलट भारत में चिकित्सा व्यय काफी हद तक निजी है। सरकार की बहुत अधिक भूमिका नहीं है। अधिकांश सरकारों के पास पर्याप्त तैयारी ही नहीं है। इसलिए क्योंकि देश में ऐसा सक्रिय सरकारी स्वास्थ्य ढांचा ही नहीं है जो 1.3 अरब भारतीयों की जरूरत पूरी कर सके। यदि देश में कोविड-19 के मरीज मौजूदा 10 गुना की दर से बढ़ते रहे तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। इतना ही नहीं परीक्षण और जांच, जरूरी बचाव उपकरण बनाने, वेंटिलेटर की आपूर्ति आदि में निजी क्षमताओं का इस्तेमाल करने में भी देर की गई है। आशा है कि भविष्य में स्वास्थ्य बजट में इसे लेकर जागरूकता दिखाई जाएगी।

देश की तंगहाल राजकोषीय स्थिति भी एक बाधा है। लंबे समय से घाटों की स्थिति बुरी ही चल रही है। राष्ट्रीय कर्ज अन्य बड़े देशों की तुलना में जीडीपी के प्रतिशत में कम है लेकिन वह फिर भी अधिक है और सरकार द्वारा खर्च बढ़ाने की राह में बाधा बना हुआ है। यही कारण है कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज न केवल दुनिया में सबसे छोटा है बल्कि एक विश्लेषक के मुताबिक इसमें से केवल 0.6 लाख करोड़ रुपये की राशि ही अलग से आवंटित होगी।

मौजूदा दौर को समाप्त होने में कई सप्ताह और महीने लग जाएंगे। इसका असर भी दीर्घकालिक हो सकता है। शेष विश्व की तरह भारत की वृद्धि दर भी तेजी से घटने की बात कही जा रही है। रोजगार और अन्य सीमित सरकारी संसाधनों के मामले में भी इसकी कीमत चुकानी होगी। यह समस्या भारत की खड़ी की हुई नहीं है लेकिन यदि हमारी सरकारी व्यवस्था ज्यादा बेहतर होती तो शायद हम इससे बेहतर तरीके से निपट पाते और नागरिकों पर इसका कम असर होता।

अजय मोहंती

देर आया पर दुरुस्त आया आरबीआई

मौजूदा हालात में किसी ने भी सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं की थी लेकिन आरबीआई ने एक ही झटके में रीपो में भी 75 आधार अंकों की कटौती कर सबको चौंका दिया है। बता रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीतिगत ब्याज दर 4.4 फीसदी के साथ इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। इसी तरह वाणिज्यिक बैंकों का नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) यानी केंद्रीय बैंक के पास रखा जाने वाला जमा अनुपात भी तीन फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर आ चुका है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि वह मौद्रिक नरमी बरतने वाले केंद्रीय बैंकों की श्रेणी में थोड़ा देर से शामिल होने के बावजूद बाजार को चौंकाने में सफल रहे। किसी ने भी इस समय सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं की थी और एक ही झटके में 75 आधार अंकों की बड़ी कटौती तो अधिकतर लोगों की अपेक्षाओं से काफी ज्यादा है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की शुक्रवार को हुई बैठक में लिए गए कई फैसले कोविड-19 महामारी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे व्यापक असर के बीच बाजार एवं वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को लेकर कायम चिंताओं को दूर करते हैं।

इस नीति में भविष्य के लिए दिखाई राह उठाए गए कदमों की ही तरह महत्त्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि आरबीआई आर्थिक वृद्धि में नई जान फूंकने के लिए परंपरागत एवं गैर-परंपरागत सभी तरह के कदम उठाएगा और इसी के साथ जहां तक जरूरी हो सामंजस्य का रुख भी बनाए रखेगा।

अब हम आरबीआई की तरफ से उठाए गए कुछ कदमों एवं उनके निहितार्थों पर गौर करते हैं:

■ नीतिगत रीपो दर 75 आधार अंकों की कटौती के साथ 5.15 फीसदी से घटकर 4.4 फीसदी पर आ गई है। इस फैसले का मतलब है कि बैंकों को अब आरबीआई से उधारी जुटाने में आने वाली लागत कम हो जाएगी।

■ रिवर्स रीपो दर में 90 आधार अंकों की भारी कटौती की गई है और अब यह चार फीसदी पर आ गई है। रिवर्स रीपो सुविधा के तहत बैंक अपने पास पड़े अतिरिक्त पैसे को आरबीआई के पास जमा कर उस पर ब्याज वसूलते हैं। ऐसे में रिवर्स रीपो दर में भारी कटौती करने का आशय यह है कि बैंक अपने पास अधिक रकम रखने से परहेज करें क्योंकि उन्हें इससे खास ब्याज नहीं मिलेगा। इसकी जगह पर वे इसका इस्तेमाल लोगों को कर्ज देकर उनसे ब्याज कमाने में करें।

■ सीआरआर में 100 आधार अंकों की बड़ी कटौती कर तीन फीसदी कर दिया गया है। बैंकों की शुद्ध मांग एवं समयबद्ध देनदारियों के लिए सीआरआर को उनकी जमाओं का एवजी प्रावधान माना जाता है। इस अनुपात में की गई कटौती एक साल के लिए प्रभावी है लेकिन बैंकों का दैनिक सीआरआर बैलेंस रखरखाव तीन महीनों में 90 फीसदी से 80 फीसदी हो गया है। बैंक सीआरआर के मद में आरबीआई के पास जो रकम रखते हैं उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है। सीआरआर में की गई इस कटौती से बैंकों के पास 1.37 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रहेगी जिसका इस्तेमाल वे कर्ज बांटने एवं निवेश उद्देश्यों के लिए कर सकेंगे।

■ आरबीआई वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रीपो नीलामी (एलटीआरओ) करता रहा है। इस बार उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक लाख करोड़ रुपये तक का लक्षित दीर्घकालिक रीपो (टीएलटीआर) नीलामी करने का फैसला किया है। इस राशि की मियाद तीन साल तक होगी जबकि इसकी लागत नीतिगत रीपो दर से जुड़ी होगी।

इस तरीके से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजारों से कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्रों एवं गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों की समान मात्रा में खरीद करने में किया जाएगा। म्युचुअल फंड हाउस एवं गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) बैंकों को ऐसे वित्तीय साधन बेच सकेंगी।

आखिर में, बैंकों को ऐसे निवेश को मार्क-टु-मार्केट (एमटीएम) के रूप में नहीं दिखाना होगा। एमटीएम अकाउंटिंग की वह प्रथा है जिसमें एक निवेश का मूल्यांकन इसकी बाजार कीमत के संदर्भ में होता है न कि जिस कीमत पर उसे खरीदा गया था। इसका मतलब है कि अगर ऐसे निवेश का मूल्य गिरता है तो भी बैंकों के बहीखाते पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) से प्रेरणा लेते हुए कहें तो एलटीआरओ और टीएलटीआरओ दोनों ही गैर-पारंपरिक उपाय हैं। निश्चित रूप से ईसीबी ने अपने एलटीआरओ को बैंक कर्ज वितरण से जोड़ दिया था, वहीं आरबीआई चाहता है कि बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने के लिए इस तरीके से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल करें।

■ बैंक आरबीआई के रीपो प्रावधान से उधारी ले सकते हैं बशर्ते उनके पोर्टफोलियो में सरकारी बॉन्ड नियामकीय जरूरत से अधिक हों। इसकी वजह यह है कि उन्हें ऐसे बॉन्ड समर्थक प्रतिभूति के तौर पर रखने की जरूरत भी पड़ सकती है। वे मार्जनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) के तहत उधारी में अपनी बॉन्ड होल्डिंग को 2 फीसदी तक घटा सकते हैं जिससे वे रीपो दर से 25 आधार अंक अधिक ब्याज दे सकते हैं। अब उन्हें एमएसएप विंडो के जरिये रकम जुटाने के लिए तत्काल प्रभाव से अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो के तीन फीसदी तक कटौती की इजाजत दे दी गई है। इस छूट की मियाद 30 जून तक रहेगी।

सीआरआर, टीएलटीआरओ विंडो और एमएसएफ छूट की यह तिकड़ी सैद्धांतिक तौर पर वित्तीय प्रणाली में करीब 3.74 लाख करोड़ रुपये डाल सकती है। इससे भी अहम यह है कि पैसों की जरूरत वाले बैंकों को अब पैसे मिलने लगेंगे। मार्च की शुरुआत से ही आर्थिक प्रणाली में प्रतिदिन औसतन तीन लाख करोड़ रुपये से भी अधिक रकम अतिरिक्त रही है लेकिन इसका वितरण असमान रहा है।

इन उपायों का असर फौरन नजर भी आने लगा। सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल करीब 30 आधार अंकों तक गिरने के बाद की गई बिक्री ने इसके प्रतिफल को बढ़ा दिया और सौदों की संख्या भी बढ़ गई। इसी तरह विसुप्त हो चुके कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में भी सीमित अवधि का प्रतिफल 100 बीपीएस चढ़ने के बाद रौनक लौट आई। बॉन्ड के भाव एवं प्रतिफल विपरीत दिशाओं में बढ़ते नजर आए। आरबीआई की नवीनतम नीति ने नियमन एवं निरीक्षण में ढील देकर बैंकों की बैलेंस-शीट का भी ध्यान रखा है। लघु वित्त बैंकों एवं सहकारी बैंकों समेत सभी वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी को सावधि कर्जों के भुगतान पर तीन महीने का अस्थायी रोक लगाया गया है। इसी तरह की छूट कार्यशील पूंजी ऋणों पर भी दी गई है। इसका मतलब है कि अगर कर्जदार किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो बैंकों को ये कर्ज एनपीए की श्रेणी में डालने की जरूरत नहीं होगी लिहाजा उन्हें इसके लिए अलग से प्रावधान भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि हालात की मांग रही तो इस कर्ज भुगतान अवकाश को आगे भी बढ़ाया जाएगा।

इस नीतिगत समीक्षा ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को चार फीसदी के दायरे में रखने के मध्यकालिक लक्ष्य को हासिल करने की आरबीआई का मंशा को फिर से दोहराया है। इसमें वृद्धि को समर्थन देने के बावजूद मुद्रास्फीति एवं वृद्धि अनुमानों को बहुत साफगोई से नहीं बयां किया गया है। वैसे इसे देखकर कोई अचंभा नहीं होता है क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ठीक यही किया है। लेकिन आश्चर्य इस पर है कि एमपीसी ने 4-2 के बहुमत से 75 आधार अंकों की कटौती करने का फैसला किया। मौजूदा हालात में भी इस समिति के दो सदस्य 50 आधार अंकों की ही कटौती के पक्ष में थे। क्या आरबीआई कुछ और कदम उठा सकता है? इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक एवं जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ परामर्शदाता हैं)

कोविड-19: राहत पैकेज का स्वागत मगर और कदमों की दरकार

देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को देखते हुए आर्थिक राहत पैकेज को लेकर उम्मीदें काफी अधिक थीं। इन आसमान छूती उम्मीदों के ही चलते गुरुवार को सरकार की तरफ से घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज को लेकर एक तरह की निराशा का भाव भी देखा जा रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक राहत पैकेज का यह ऐलान एक स्वागत-योग्य एवं बेहद जरूरी कदम है। राहत देने के लिए उठाए गए इस पहले कदम से लॉकडाउन में करोड़ों गरीब भारतीयों को पेश आ रहीं मुश्किलें कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बुधवार से शुरू हुए तीन हफ्तों के लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए अभी बहुत कुछ और किए जाने की जरूरत है और आने वाले हफ्तों में राहत देने वाले ऐसे कई अन्य फैसलों की भी जरूरत होगी। इसकी वजह है कि आने वाले दिनों में ही कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का आर्थिक असर अधिक साफ हो पाएगा।

इस राहत पैकेज को लेकर बड़ी उम्मीदें जगाने वाले पहलुओं को लेकर कोई गलती न करें। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने गत 19 मार्च को कोरोनावायरस के मसले पर पहली बार देश को संबोधित करते हुए कहा था कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यबल बनाया गया है जो इस महामारी से निपटने के लिए जरूरी आर्थिक कदमों के बारे में फैसला करेगा।

उसके बाद से ही हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि सरकार के इस राहत पैकेज का आकार एवं स्वरूप कैसा होगा?

इस पैकेज के बारे में अगले चार दिनों तक कोई प्रगति देखने को नहीं मिली। फिर 23 मार्च को सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन कर कुछ आर्थिक कानूनों एवं प्रावधानों के अनुपालन में ढील देने की घोषणा की। राहत पैकेज के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने उसी शाम को एक बार फिर देश को संबोधित किया लेकिन उसमें भी आर्थिक पैकेज का कोई जिक्र नहीं हुआ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े उपकरणों के लिए 15,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा जरूर की थी। देश भर में 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन करने का फैसला एकदम सही था लेकिन इसके आर्थिक दुष्प्रभावों का भी अंदाजा सबको था। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही आर्थिक पैकेज की घोषणा न होना यह दर्शाता है कि इस विपदा से कितने खराब ढंग से निपटा जा रहा है?

इस बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए न्यूनतम 5 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिए जाने की चर्चा शुरू कर दी। अगर ऐसा होता तो यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2 फीसदी से थोड़ा अधिक ही होता।

दिल्ली डायरी
ए के भट्टाचार्य

> अमेरिका ने हाल में 2 लाख करोड़ डॉलर के वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की है जो उसके जीडीपी का 10 फीसदी है। लिहाजा, अमेरिका और भारत में घोषित कोविड-19 राहत पैकेजों की तुलना फौरन शुरू हो गई। अगर भारत सरकार अमेरिका की तर्ज पर अपना राहत पैकेज घोषित करती तो उसका आकार कितना होता? क्या इसका आकार 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक होता?

दरअसल अमेरिका ने हाल में 2 लाख करोड़ डॉलर के वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की है जो उसके जीडीपी का 10 फीसदी है। लिहाजा, अमेरिका और भारत में घोषित कोविड-19 राहत पैकेजों की तुलना फौरन शुरू हो गई। अगर भारत सरकार अमेरिका की तर्ज पर अपना राहत पैकेज घोषित करती तो उसका आकार कितना होता? क्या इसका आकार 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक होता? लेकिन यह बात भी तो है कि हमारी तुलना में अमेरिका इस महामारी की चपेट में कहीं अधिक है। इसके अलावा अमेरिका से भारत की तुलना करना भी उचित नहीं है। लेकिन गुरुवार को घोषित कुल राहत पैकेज भारत के जीडीपी के एक फीसदी से भी कम है। यह अमेरिका के राहत पैकेज या चिदंबरम द्वारा सुझाए गए आंकड़े के आसपास भी नहीं है। इस तरह की तुलनाएं और पैकेज घोषित करने में लगा सात दिनों का वक्त ही शायद इस बात के लिए जिम्मेदार है कि अधिकतर लोग इससे खुश नहीं हैं और अब अगले दौर के पैकेज की मांग कर रहे हैं।

वैसे इस पैकेज को लेकर दो अन्य बिंदुओं पर भी गौर करना चाहिए। पहला, यह पैकेज केवल गरीब लोगों की चिंताओं का ध्यान रखता है, मसलन, प्रवासी मजदूर, छोटी फर्मों एवं निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले संगठित कामगार, महिलाएं, किसान और स्वास्थ्य कर्मचारी। अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गों- खासकर विनिर्माण क्षेत्र और सेवा-प्रदाता कंपनियों पर लॉकडाउन का असर बहुत अधिक होगा। इन क्षेत्रों के लिए भी एक आर्थिक पैकेज के ऐलान की तत्काल जरूरत है।

दूसरा, आर्थिक पैकेज स्वास्थ्य देखभाल का ढांचा खड़ा करने या उसे सशक्त करने की जरूरत को लेकर चुप नहीं रह सकता है। देश में जल्द ही परीक्षण सुविधाएं बड़े स्तर पर शुरू करने और कोरोना का प्रसार होने पर इसकी चपेट में आने वाले लोगों के समुचित इलाज की जरूरत है। साफ है कि दो अन्य आर्थिक राहत पैकेज की जरूरत है। गुरुवार को घोषित हुआ राहत पैकेज काफी नहीं होगा।

कानाफूसी

मशविरों की होड़

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद केंद्र सरकार को लगातार ऐसी सलाह मिल रही हैं कि वह गरीबों को इस लॉकडाउन के आर्थिक दुष्प्रभावों से किस प्रकार बचाए। ये मशविरे राजनीतिक दलों और मजदूर संगठनों की ओर से आ रहे हैं। वाम समर्थित श्रम संगठनों ने इसकी शुरुआत की। इन संगठनों ने इस सप्ताह के आरंभ में केंद्र को ऐसे उपायों की लंबी सूची भेजी जो उनके हिसाब से गरीबों के बचाव में उपयोगी हो सकती थी। इस बात से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध और खुद को सबसे बड़ा मजदूर संगठन कहने वाले भारतीय मजदूर संघ को शर्मिंदगी महसूस हुई। बहरहाल एक दिन बाद उसने भी अपनी ओर से संभावित उपायों की एक सूची तैयार की। जाहिर है ये उपाय भी काफी हद तक पहले वाले उपायों जैसे ही थे।

शर्मिंदगी का सबब

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों अनजाने ही अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिए शर्मिंदगी पैदा कर दी। राहुल गांधी न्याय योजना के हिमायती रहे हैं। यह योजना गरीबों को न्यूनतम आय समर्थन की वकालत करती है। लॉकडाउन के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि केंद्र सरकार को प्रत्येक जनधन खाते, पीएम किसान खातों और हर पेंशन खाते में 7,500 रुपये स्थानांतरित करने चाहिए और निःशुल्क राशन वितरित करना चाहिए। हालांकि पिछले एक साल के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों में भी यह योजना लागू कराने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रही क्योंकि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी तनावपूर्ण है। ऐसे सवाल भी उठाए गए कि यदि भाजपा ने पूछा कि कांग्रेस अपने शासन वाले राज्यों में इस योजना को क्यों नहीं लागू किया तो क्या जवाब दिया जाएगा?

आपका पक्ष

कोरोना के कहर से किसान चिंतित

कोरोनावायरस का कहर आज पूरे विश्व में छाया हुआ है। प्रतिदिन आ रही खबरों से पता चलता है कि भारत में भी इसका तेजी से प्रसार हो रहा है। इसकी वजह से देश में हुए लॉकडाउन के कारण न केवल तमाम उद्योगों, श्रमिकों, शेयर बाजार को आर्थिक रूप से लाचारी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इसका प्रभाव उन किसानों पर भी सर्वाधिक पड़ने वाला है जो छोटी जोत के हैं या दूसरे के खेत पर निर्भर हैं। किसानों को पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से फसल नुकसान का दर्द पहले से ही था। वहीं 21 दिनों तक लॉकडाउन से किसान अधिक चिंतित हैं। उन्हें अब इस बात का डर है कि खेतों में खड़ी फसल बरबाद न हो जाए। किसानों की चिंता भी जायज है क्योंकि ओलावृष्टि से बची फसल भले ही

महाराष्ट्र में महिला से हाथ जोड़ घर लौट जाने की अपील करती महिला ट्रैफिक पुलिस

आर्थिक नुकसान की उतनी भरपाई न कर पाए लेकिन यह देश को खाद्यान्न संकट से बचा सकती है। इन सब के बावजूद यह भी आवश्यक है कि किसान अपनी और देश की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इस लॉकडाउन को सफल बनाने में सहयोग करें और सरकार के निर्देशों के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतें।

सौरभ सिंह विराट, बांदा

कोरोना संकट में आलोचना नहीं करें

कोरोना संकट में सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की आलोचना करने वाले लोगों को दोबारा विचार करना चाहिए। हाल में एयर इंडिया के कर्मचारियों ने अन्य देशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी में सराहनीय भूमिका अदा की। लेकिन उनके परिवारजनों को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। शायद शिकायत करने वाले लोग भूल गए हैं कि इन्हीं जांबाज सदस्यों की वजह से कितने परिवारों ने राहत की सांस ली। कोविड-19 के केंद्र बिंदु वुहान से एयर इंडिया के दो विमानों से सैकड़ों लोगों को दिल्ली लाया गया जिनमें सात अन्य देश के यात्री भी शामिल थे। इटली में कोरोना के सबसे ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए तथा मौत का आंकड़ा भी अन्य देशों से अधिक है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी रोम से 253 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया।

उद्देश्य कुमार, मणिपाल

सभी स्तर पर नजर आ रही सक्रियता

कोरोनावायरस रोकने के लिए सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। मास्क, सैनिटाइजर जैसे जरूरी उत्पादों की कालाबाजारी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। विमानों का परिचालन बंद कर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया। राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। डॉक्टर, मीडिया ने प्रतिबद्धता दिखाई और निरंतर सेवा कर रहे हैं।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, उज्जैन

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

चंडीगढ़ | 28 मार्च 2020 शनिवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

फोटोः दलीप कुमार

प्रवासी मजदूरों की बढ़ी मुसीबत

देश में लॉकडाउन शुरू होने के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हुआ

सोमेश झा

दुर्गा प्रसाद दिल्ली में कपड़ा बनाने वाली एक इकाई में काम करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाले अपने परिवार को पिछले शनिवार को फोन करके कहा कि उनकी फैक्टरी अगले 15 दिन के लिए बंद हो रही है और वह घर वापस आ रहे हैं। इसके एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आधिकारिक तौर पर बंदी की घोषणा कर दी। ओखला औद्योगिक क्षेत्र में साइकिल पर बैठे 34 साल के प्रसाद ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'मेरे मालिक ने मुझे बंदी के दौरान पैसा देने से इनकार कर दिया जिसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया है। मैं घर जा रहा हूं। प्रसाद की तरह देश में करीब 47.1 करोड़ कामगार हैं जिन्होंने आज तक कभी खुद को इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया। इनमें से करीब 81 फीसदी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है और जो जटिल श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हैं।

देश में करीब 47.1 करोड़ कामगार हैं, जिनमें करीब 81 फीसदी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं

निर्माण क्षेत्र में मजदूरी करने वाले 26 साल के पिंटू सिंह को भी छोटे-मोटे काम की तलाश है। ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में फंसे बाकी मजदूरों के साथ आराम कर रहे हैं। रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन वह आनन-फानन में रेवाड़ी से बिहार के चंपारण में अपने घर को निकले। लेकिन लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंस गए। सिंह को रोज 600 रुपये की दिहाड़ी मिल रही थी। उन्होंने कहा, 'मैं अपना सबकुछ छोड़कर आ गया। मुझे ठेकेदार से 7,000 रुपये लेने थे लेकिन मैंने छोड़ दिया। ठेकेदार जाने नहीं दे रहा था। उसने कहा कि वह खाना देगा लेकिन दिहाड़ी नहीं देगा। इस मुश्किल समय में मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं।' वह केवल 2,000 रुपये लेकर वहां से चले आए।

सामाजिक सुरक्षा का अभाव

कोविड-19 से देश के कामगार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं लेकिन देश में अधिकांश कामगार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं हैं। कई दूसरे देशों में अधिकारों पर आधारित नीति के तहत सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है लेकिन इसके उलट भारत रोजगार आधारित नीति पर अटका हुआ है। देश में सामाजिक सुरक्षा उन्हीं इकाइयों तक सीमित है जो न्यूनतम अनिवार्य संख्या में कामगारों को काम पर रखती हैं। उदाहरण के लिए कामगारों को उन्हीं इकाइयों में स्वास्थ्य और दूसरी तरह के बीमा का लाभ मिलता है जिनमें कामगारों की संख्या कम से कम 10 हो। उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जरिये यह सुविधा दी जाती है। भविष्य निधि की सुविधा भी तभी मिलती है जब किसी प्रतिष्ठान में काम करने वालों की संख्या 20 या उससे अधिक हो। इसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। यह लाभ भी कम ही लोगों को नसीब है। 2013-14 की आर्थिक जनगणना के मुताबिक 98.6 फीसदी प्रतिष्ठानों में 10 से कम कामगार काम करते हैं। इसका मतलब कि इन प्रतिष्ठानों में काम करने वालों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। प्रसाद और सिंह कामगारों की इसी श्रेणी का हिस्सा हैं।

बंद से पलायन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 24 मार्च को 21 दिन तक पूरे देश को लॉकडाउन करने की घोषणा की थी तो उससे पहले ही देश के 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में से 30 इसे लागू कर चुके थे। महाराष्ट्र ने 31 मार्च तक राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन की घोषणा की तो उसके बाद बड़ी संख्या में कामगारों का पलायन शुरू हुआ। घर जाने की अफरातफरी में रेलवे स्टेशनों पर हजारों कामगार देखकर सरकार के भी पसीने छूटने लगे। देश में प्रवासी कामगारों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक यह 10 करोड़ हो सकता है। संसद में अक्सर इस सर्वेक्षण का हवाला दिया जाता है। यह देश में कामगारों की कुल आबादी का करीब 20 फीसदी हिस्सा है। कई दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के जोर पकड़ने के बाद कामगारों के पलायन में भी तेजी आई। जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक 1991-2001 में प्रवासी कामगारों की संख्या में हर साल जहां 2.4 फीसदी का इजाफा हुआ, वहीं 2001-11 के दौरान यह वृद्धि 4.5 फीसदी रही।

सुरक्षा कवच का अभाव

- कामगारों को उन्हीं इकाइयों में स्वास्थ्य और अन्य बीमा लाभ मिलते है जिनमें कामगारों की संख्या कम से कम 10 हो
- भविष्य निधि भी तभी मिलती है जब किसी प्रतिष्ठान में काम करने वालों की संख्या 20 या उससे अधिक होती है
- देश में 98.6 फीसदी प्रतिष्ठानों में 10 से कम कामगार करते हैं काम

कोई अनुबंध नहीं

सरकार में नियोक्ताओं को कामगारों से घर के काम करने की अनुमति देने और उनके वेतन में कटौती नहीं करने को कहा है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे घरों में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखें और अगर वे काम पर नहीं आते हैं तो भी उन्हें पूरा भुगतान किया जाए।

घर से काम की अपील से ऐसे कामगार तो बच जाएंगे जिनको नियमित वेतन मिलता है। लेकिन 30 साल की जीनत के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। वह सीलमपुर में कपड़े की फैक्टरी में काम करती थीं जहां उन्हें हर महीने 6,000 रुपये मिलते थे। उनके मालिक ने उन्हें भुगतान अवकाश देने से मना कर दिया। जीनत के पास कार्य अनुबंध नहीं है और अब उनके पास उत्तर प्रदेश में अपने घर लौटने की कोशिश करने के सिवा कोई चारा नहीं है। आनंद विहार बस अड्डे पर अपने परिवार के पास बैठी जीनत ने कहा, 'मुझे पिछले तीन महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली। अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही बंद है लेकिन जीनत को उम्मीद है कि उनके घर तक जाने का कोई न कोई जुगाड़ हो जाएगा।' राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2017-18 में किए गए सांविधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक जीनत की तरह देश में दो-तिहाई कामगार ऐसे हैं जिन्हें नियमित वेतन मिलता है लेकिन उनके पास कोई लिखित अनुबंध नहीं है। लिखित अनुबंध में रोजगार की शर्तों का साफ-साफ उल्लेख होता है। लेकिन इसके अभाव में जीनत जैसी कामगारों के लिए बिना वेतन के नौकरी से हटाए जाने का जोखिम होता है।

छंटनी का अधिकार

1947 के औद्योगिक विवाद कानून में उन नियमों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत कंपनियां संगठित कामगारों की छंटनी कर सकती हैं। देश में 100 से कम कामगारों वाली कंपनियों के लिए छंटनी पर कोई रोक नहीं है। इसमें सरकार के पास हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उन कंपनियों को छंटनी के लिए सरकार के मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है जिनके कर्मचारियों की संख्या 300 तक है। लेकिन ये नियम सेवा क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं और इसके दायरे में केवल विनिर्माण, बागान और खनन क्षेत्र आते हैं। अगर कोई कंपनी छंटनी करना चाहती है ते उसे कामगारों को तीन हफ्ते के वेतन का आधा हिस्सा देना होगा। लेकिन 50 से कम कामगारों वाली कंपनी को यह मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। श्रम कानूनों के कुछ पुराने प्रावधान कामगारों के जख्मों पर नमक का काम करेंगे। उदाहरण के लिए, भारत में अगर कोई कामगार लंबे समय से बीमार है तो उसके निकालने के लिए कंपनियों के मुआवजे का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। दूसरे कामगारों को छंटनी पर मुआवजा मिलता है। इसके तहत कामगार ने जितने साल काम किया है, उसके हिसाब से हर साल 15 दिन के काम के बराबर मुआवजा मिलता है।

कामगारों को स्वास्थ्य लाभ

कम से कम 10 कामगार रखने वाले प्रतिष्ठान ईएसआई योजना के अधीन आते हैं। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी बराबर योगदान करते हैं। ईएसआई देश की सबसे बड़ी अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजना है और दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। नीति आयोग के मुताबिक इसके लाभार्थियों की संख्या 8.6 करोड़ है और यह कम आय वाले संगठित कामगारों के लिए है। लेकिन ईएसआई का चिकित्सा ढांचा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है।

समय पर हस्तक्षेप

मंगलवार को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें खर्च नहीं किए गए 52,000 करोड़ रुपये के उपकर कोष से निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के खाते में पैसा डालने का आग्रह किया। राज्यों के पास अपना खुद का कोष है और साथ ही उनके पास निर्माण क्षेत्र के मजदूरों की सूची भी है। इसलिए उनकी पहचान करना मुश्किल काम नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तत्काल राहत के रूप में पहले ही निर्माण क्षेत्र के हर पंजीकृत मजदूर के खाते में 3,000 रुपये डालने की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली ने भी हर मजदूर को 5,000 रुपये और हिमाचल प्रदेश ने बतौर एकमुश्त राहत ऐसे मजदूरों को 1,000 रुपये देने का ऐलान किया है।

लेकिन निर्माण क्षेत्र के मजदूर अन्नू को यह राहत नहीं मिलेगी क्योंकि एक ठेकेदार के जरिये काम पर आए थे। भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कानून, 1996 के तहत आधिकारिक पहचान पत्र नहीं है जिससे वह 35 लाख पंजीकृत मजदूरों की तरह लाभ पाने के हकदार नहीं है। मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले अन्नू पिछले करीब एक दशक से दिल्ली में रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर निर्माण कार्य किया है। कुछ दिन पहले जब काम बंद हुआ तो उनकी जेब में केवल 1,500 रुपये थे। बुधवार को उन्होंने चौथा दिन सड़क पर गुजारा। जब वह सराय काले खां बस स्टेशन के करीब फुटपाथ पर सोए थे तो किसी ने उनके पैसे चुरा लिए।

मोदी के लॉकडाउन भाषण को 20 करोड़ ने देखा

सोहिनी दास

कोरोनावायरस के गहराते संकट के बीच करीब 19.7 करोड़ भारतीयों ने 24 मार्च की शाम को देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना जिसमें उन्होंने 21 दिनों तक देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसका प्रसारण 201 चैनलों ने किया और यह देश का सबसे बड़ा न्यूज इवेंट बन गया।

ईंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फाइनल को 13.3 करोड़ दर्शकों ने देखा था और उसके मुकाबले मोदी के संबोधन को ज्यादा लोगों ने देखा। इसने दर्शकों की संख्या के लिहाज से प्रधानमंत्री के 19 मार्च को दिए गए संबोधन को भी पीछे छोड़ दिया जिस दिन उन्होंने 'जनता कर्फ्यू' लगाने का ऐलान किया था। इस दिन उन्हें कुल 8.3 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा था। लॉकडाउन की घोषणा नोटबंदी की घोषणा के मुकाबले लगभग चार गुना बड़ा इवेंट बन गया। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) निल्सन रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी की घोषणा को 5.7 करोड़ दर्शकों ने देखा था। बार्क टीवी के दर्शकों की संख्या मापने वाली एक संस्था है।

हाल के दिनों में किसी अन्य इवेंट या घटना के मुकाबले देश के लोगों का ध्यान कोविड-19 को लेकर ज्यादा बढ़ा है। इस कारण टीवी दर्शकों की संख्या बढ़ी है। अरबों लोग घरों में बैठे हैं। ऐसे में औसतन रोजाना टीवी दर्शकों की संख्या में 3.2 करोड़ का इजाफा हुआ है और 59.2 करोड़ में से हर दर्शक रोजाना तीन घंटे से 51 मिनट तक टीवी देखता हैं।

बार्क ने कोविड-19 महामारी फैलने से पहले की अवधि (11 जनवरी से 31 जनवरी) की तुलना कोविड-19 के मामले बढ़ने वाले समय (14 मार्च से 20 मार्च तक) से की है। जहां तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है इसने दर्शकों के रुझान का अंदाजा दिया है। इस अवधि के दौरान साप्ताहिक आधार पर टीवी देखने के मिनट में 8 फीसदी की उछाल आई जबकि रोजाना टीवी देखने की औसत तादाद में 6 फीसदी की तेजी दिखी। वहीं हर दर्शक के औसत वक्त में भी 2 फीसदी की बढ़त रही। इस अवधि के दौरान हिंदी भाषी क्षेत्रों के बाजार में टीवी देखने के समय में 10 फीसदी की तेज बढ़त दिखी।

प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी

करीब 2 साल से 14 साल उम्र वर्ग के दर्शकों (बच्चों) की तादाद में भी 20 फीसदी की उछाल देखी गई। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। इनमें से करीब 83 फीसदी समाचार देख रहे हैं। इनमें से करीब 40 फीसदी बच्चों वाली सामग्री देख रहे हैं और केवल 11 फीसदी बच्चे ही सामान्य मनोरंजन चैनल (जीईसी) देख रहे हैं।

कोरोना के कारण नए एपिसोड की शूटिंग नहीं हो रही है, जिससे सामान्य मनोरंजन चैनलों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इन चैनलों पर दर्शकों द्वारा बिताए जाने वाले रोजाना औसत समय में भी 5 फीसदी की कमी आई है। विभिन्न श्रेणियों में समाचार में सबसे ज्यादा बढ़त दिखी है और समाचार के लिए खर्च किए जाने वाले रोजाना औसत समय में 17 फीसदी की बढ़त है जबकि बच्चों के चैनल (11 फीसदी) और फिल्मों (4 फीसदी) का स्थान इसके बाद आता है। खेल श्रेणी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है क्योंकि इसमें कोई नई सामग्री नहीं है। इस श्रेणी पर दर्शकों द्वारा दिए जाने वाले रोजाना औसत वक्त में 56 फीसदी की गिरावट आई है।

बार्क इंडिया के सीईओ अधिकारी सुनील लूला का कहना है देश में समाचार श्रेणी में विज्ञापन की तादाद भी बढ़ी है। विज्ञापन मुक्त कॉमर्शियल टाइम (एफसीटी) में 13 फीसदी की तेजी है। इसके बाद सबसे ज्यादा तेजी सोशल एडवर्टाइजिंग (147 फीसदी), बैंकिंग (47 फीसदी), फूड ऐंड बेवरिज (36 फीसदी) और सेवा क्षेत्र (22 फीसदी) दिखी।

प्रधानमंत्री के संबोधन को कितनों ने देखा

तारीख	प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन	चैनल	दर्शकों की संख्या (करोड़)	देखने के मिनट (करोड़ में)
8 नवंबर 2016	नोटबंदी	114	5.7	84.2
8 अगस्त 2019	अनुच्छेद 370	163	6.5	93.4
19 मार्च 2020	कोविड-19 जनता कर्फ्यू	191	8.3	127.5
24 मार्च 2020	कोविड-19 पूर्ण लॉकडाउन	201	19.7	389.1

स्रोत : बार्क नील्सन रिपोर्ट
* दर्शक संख्या के ये आंकड़े शुरुआती दर्शक अनुमानों पर आधारित हैं और इनमें अंतिम आंकड़ों में बदलाव हो सकता है।

पृष्ठ 1 का शेष

कामगारों की मदद की तैयारी में सरकार

दिल्ली से लेकर तेलंगाना और केरल तक मजदूर सड़कों पर पैदल चलते दे रहे हैं दिखाई फोटो : पीटीआई

कोरोनावायरस का प्रसार रोकने के लिए इस सप्ताह के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार से पूरे देश में 21 दिनों के बंद की घोषणा की थी। इससे देश में अंतर-राज्यीय सीमाओं पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। रेलगाड़ियां समेत विमानों का परिचालन भी 14 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। देश में एक तरह से निषेधाज्ञा लगा दी गई है और केवल आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की ही अनुमति दी गई है। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद उद्योग बंद होने लगे, जिसके बाद बाहर से आए मजदूर विभिन्न शहरों से दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने घर जाने लगे। दिल्ली से लेकर तेलंगाना और केरल तक ऐसे मजदूरों को सड़कों पर पैदल चलते देखा गया। इस बीच, देश में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस इन मजदूरों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। हालत इतनी खराब है कि गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना से आ रहे दो कंटेनर ट्रकों में 300 से अधिक कामगारों को आते हुए पकड़ा।

कोरोनावायरस से बदलीं दर्शकों की आदतें

लॉकडाउन से समाचार चैनलों, गेमिंग ऐप और बच्चों की सामग्री की खपत बढ़ी जबकि रेडियो, आउट ऑफ होम, प्रिंट और मल्टीप्लेक्स को घाटा हुआ

विवेट सुजन पिंटो और सोहिनी दास

कोरोनावायरस फैलने के कारण लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे घरेलू मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में पिछले एक महीने के दौरान बड़ा बदलाव आया है। ईवाई जैसी कंसल्टेंसी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने शुक्रवार को कहा कि 16 मार्च को चरणबद्ध लॉकडाउन शुरू होने के सप्ताह में समाचार चैनलों, गेमिंग ऐप और बच्चों की सामग्री की खपत बढ़ी है, जबकि रेडियो, आउट ऑफ होम, प्रिंट और मल्टी प्लेक्स को नुकसान हुआ है।

ईवाई का अनुमान है कि एक महीने के लॉकडाउन से इस कैलेंडर वर्ष में इस क्षेत्र की वृद्धि सपाट रहेगी, जबकि संक्रमण फैलने से पहले इस कंसल्टेंसी ने वर्ष 2020 में 8 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया था। ईवाई ने शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ मिलकर जारी मीडिया एवं मनोरंजन रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि 2020 में इस बाजार का कुल आकार 1.96 लाख करोड़ रुपये रहेगा, जो कोरोनावायरस के फैलने से पहले के आकलन पर आधारित है। वर्ष 2019 में मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र का आकार 1.82 लाख करोड़ रुपये था।

ईवाई इंडिया में लीडर (मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र) आशीष फेरवानी ने कहा कि अगर लॉकडाउन की अवधि को दो महीनों के लिए बढ़ाया गया तो स्थिति खराब हो सकती है और वृद्धि 10 से 12 फीसदी घट सकती है। वहीं अगर बंद तीन महीने तक बढ़ाया गया तो वृद्धि में गिरावट 20 से 25 फीसदी रह सकती है।

फेरवानी ने कहा, 'इस समय कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल है। आगे चलकर ही पूरे असर का पता चल पाएगा।' उन्होंने कहा, 'डिजिटल दर्शकों का उज्ज्वल भविष्य है और प्रसारकों को आगामी महीनों में नए सामान्य से तालमेल कायम करना होगा। वे पहले ही टीवी पर नई सामग्री खत्म होने के कारण पुरानी सामग्री की रीपैकेजिंग कर रहे हैं और ओवर दी टॉप सामग्री को टीवी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।'

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 16 मार्च से 22 मार्च के बीच देश में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन शुरू होने के बीच टेलीविजन की पहुंच इससे पहले के सप्ताह के मुकाबले छह फीसदी बढ़ी है।

बार्क ने कहा कि इसके अलावा 16 से 22 मार्च के बीच औसत दैनिक दर्शकों की तादाद लॉकडाउन से पहले के सप्ताह की तुलना में 3.2 करोड़ बढ़ी और दर्शकों ने सप्ताह के दौरान रोजाना 3 घंटे 51 मिनट टीवी देखते हुए बिताए। इसमें फिल्म, किड्स और समाचार सामग्री की

अहम भूमिका रही।

बार्क ने कहा कि दूसरी ओर डिजिटल खपत तेजी से बढ़ी है। 16 से 22 मार्च तक के सप्ताह में समाचार ऐप के दर्शक आठ फीसदी बढ़े। इस अवधि में प्रत्येक यूजर द्वारा समाचार ऐप पर बिताए गए समय में भी 17 फीसदी बढ़ोतरी हुई। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान गेमिंग ऐप के यूजर दो फीसदी बढ़े। वहीं इस अवधि मेमं प्रत्येक यूजर द्वारा गेमिंग ऐप पर बिताए गए समय में 11 फीसदी इजाफा हुआ।

उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि मध्यम अवधि में टेलीविजन दर्शकों की संख्या में वृद्धि का रुझान जारी रहेगा। एक मीडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कुल मिलाकर सामान्य मनोरंजन चैनलों (जीईसी) पर दर्शकों के लिहाज से कुछ असर पड़ा है क्योंकि नई सामग्री का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन यह

मीडिया व मनोरंजन क्षेत्र की वृद्धि चालू कैलेंडर वर्ष में सपाट रहने के आसार

संकट दूर होने के बाद समर्पित दर्शक फिर से सामान्य मनोरंजन चैनलों पर लौट आएंगे, जिससे विज्ञापनदाता भी आ जाएंगे।'

विशेषज्ञों ने कहा कि सब टीवी (हास्य) एनडीटीवी गुडटाइम्स (यात्रा एवं जीवन शैली) फूड एवं इन्फोटेनमेंट चैनल (जैस फूड फूड, फॉक्स लाइफ, सोनी बीबीसी अर्थ) परंपरागत रूप से लोकप्रिय चैनलों के रिपीट प्रसारण से फले-फूले हैं। यह रुझान निकट भविष्य में भी बने रहने के आसार हैं।

बार्क का कहना है कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर चैटिंग और नेटवर्किंग में ज्यादा समय बिता रहे हैं। इसमें 16 मार्च से 22 मार्च के सप्ताह में पहले के सप्ताह की तुलना में 23 से 25 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।

बार्क ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत लगभग सभी सोशल नेटवर्किंग ऐप समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान न केवल प्रत्येक यूजर द्वारा बिताए गए समय में अहम बढ़ोतरी हुई है बल्कि अवधि के दौरान प्रति यूजर सेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके विपरीत शॉपिंग, यात्रा और फूड ऐप ने सप्ताह में यूजर की संख्या और बिताए गए समय में भारी गिरावट दर्ज की है।

विश्लेषकों का कहना है कि मल्टीप्लेक्स के लिए आगे मुश्किल वक्त रहने के आसार हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि उसका अनुमान है कि लॉकडाउन मई तक जारी रहेगा और मल्टीप्लेक्स का परिचालन जून 2020 से ही शुरू हो पाएगा।

इस ब्रोकरेज ने कहा, 'मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों के प्रबंधन से हमारी बातचीत और उनके द्वारा कही गई बातों से पता चलता है कि मल्टीप्लेक्स किराये की अहम लागत (जिसका कुल निश्चित लागत में 44 से 45 फीसदी हिस्सा है) से खुद को बचाने के लिए फोर्स मैजर खंड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मॉल और मल्टीप्लेक्स के बंद होने का मतलब है कि कार्मिकों, मरम्मत और बिजली की लागत जैसी अन्य निश्चित लागतों में बचत होगी।'

फेरवानी ने कहा कि आगामी महीनों के दौरान फिल्मों की डिजिटल रिलीज में बढ़ोतरी होगी। ऐसा विशेष रूप से छोटे निर्माता करेंगे। हालांकि बड़े प्रॉडक्शन हाउस कारोबार के लिए थियेटरों में रिलीज पर ही भरोसा करेंगे।